Useful For Prelims

Date: 23 December 2025

आजीवन देश सेवा के प्रति समर्पित रहे राशबिहारी घोष

राशबिहारी घोष का जन्म 1845 में आज ही बंगाल के बर्धमान में हुआ था। 1867 में वकील के रूप में पेशेवर जीवन की शुरुआत की। 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किया और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया, जिसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना शामिल था। शिक्षा को मुक्ति की आधारशिला मानने वाले राशबिहारी घोष ने वकालत से अर्जित धन का अधिकांश हिस्सा दान में दे दिया था। जादवपुर में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना के लिए उन्होंने 13 लाख रुपये का योगदान दिया, जो बाद में जादवपुर विश्वविद्यालय बना। स्कूल और अस्पताल भी स्थापित किए।

Dainik Jagaran Page No-14

भारत–न्यूजीलैंड के बीच एफटीए वार्ता संपन्न

दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने की घोषणा, इस समझौते से किसानों, युवाओं और एमएसएमई को होगा फायदा

- व्यापार समझौते से भारत का न्यूजीलैंड को 100 प्रतिशत निर्यात शुल्क मुक्त हो जाएगा
- हर साल 47 अरब डालर का आयात करता है न्यूजीलैंड, भारतीय निर्यात बढ़ेगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: वैश्विक कारोबार के पटल पर भारत की महत्ता लगातार बढ़ती जा रही है। इसी का परिणाम है कि भारत ने एक सप्ताह में दो देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) किए हैं। सोमवार को भारत और न्यूजीलैंड ने प्रधानमंत्रियों ने टेलीफोन पर बातचीत के बाद एफटीए वार्ता पूरी होने की घोषणा की। पिछले सप्ताह ही भारत ने ओमान के साथ कंप्रेहेंसिव इकोनामिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीपा) किया गया था। 49 हजार डालर प्रति व्यक्ति आय वाले देश न्यूजीलैंड के साथ एफटीए होने से कृषि पदार्थ से लेकर सभी रोजगारपरक सेक्टर से जुड़े उत्पाद अब न्यूजीलैंड को बिना शुल्क निर्यात हो सकेंगे। इससे किसान व एमएसएमई को बड़ा फायदा मिलेगा।

भारत ने न्यूजीलैंड के लिए भी अपने कृषि व डेयरी बाजार को नहीं खोला है। लेकिन सेब, कीवी, मनुका मधु के साथ न्यूजीलैंड के वाइन को शुल्क में भारत ने बड़ी राहत दी है। इससे ये उत्पाद अब भारत में सस्ते होंगे। न्यूजीलैंड सेब, कीवी व डेयरी सेक्टर में भारतीय उत्पादकता को बढ़ाने में अपनी टेक्नोलाजी से मदद करेगा। न्यूजीलैंड से आयात होने वाले कोकिंग कोयला, लकड़ी व स्क्रैप मैटेरियल पर शुल्क को हटा दिया गया है। इससे भारतीय मैन्यूफैक्चरिंग को सस्ते में कच्चे माल मिलेंगे। एफटीए के तहत अगले 15 सालों में न्यूजीलैंड भारतीय मैन्यूफैक्चरिंग में 1.8 लाख करोड़ रुपये का निवेश भी करेगा। समझौते के तहत भारत का 100 प्रतिशत व न्यूजीलैंड का 95 प्रतिशत निर्यात शुल्क मुक्त हो जाएगा।

सालाना 47 अरब डालर का आयात करने वाले देश न्यूजीलैंड के साथ भारत का वस्तु कारोबार वित्त वर्ष 2024-25 में सिर्फ 1.3 अरब डालर का रहा है। इसलिए टेक्सटाइल, लेदर आइटम, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स व ज्वेलरी, दवा, केमिकल्स, प्लास्टिक जैसे उत्पाद का निर्यात बढ़ाने का भारतीय कारोबारियों को बड़ा अवसर मिलने जा रहा है। भारतीय वस्तुओं पर अभी 2-10 प्रतिशत का शुल्क लगता है जो शून्य हो जाएगा। एफटीए पर अगले तीन माह में हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसके एक-दो माह के भीतर अमल शुरू हो जाएगा।

> सिर्फ नौ महीनों में पूरा हुआ यह ऐतिहासिक कदम दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करने की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और साझा महत्वाकांक्षा को दिखाता है।
> **पीएम नरेन्द्र मोदी**

नई दिल्ली में सोमवार को न्यूजीलैंड के मंत्री टाड मैक्ले के साथ बैठक के दौरान केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल • प्रेट्र

कुशल श्रमिकों के लिए खुले न्यूजीलैंड के दरवाजे

कुशल श्रमिकों की कमी से जूझ रहे न्यूजीलैंड ने भारतीय छात्र व कामगारों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। स्वास्थ्य, आइटी, पर्यटन समेत 118 प्रकार के सेवा निर्यात पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा। न्यूजीलैंड में पढ़ने जाने वाले भारतीय छात्रों को सप्ताह में 20 घंटे काम करने की छूट होगी। इस मौके पर वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यह एक समग्र एफटीए है जिससे किसान, एमएसएमई, सर्विस सेक्टर व भारतीय युवाओं को तरक्की करने का मौका मिलेगा। इस एफटीए वार्ता को मात्र नौ माह के रिकार्ड समय में वाणिज्य मंत्रालय की महिला अधिकारियों की टीम ने पूरा किया है।

मात्र कुछ वर्षों में ही सात मुक्त व्यापार समझौते

भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती को देखते हुए दुनिया का हर विकसित देश अब भारत के साथ व्यापार समझौता करना चाहता है। यही कारण है कुछ वर्षों में ही मारीशस, आस्ट्रेलिया, यूएई, एफ्टा देश (स्विट्जरलैंड, नार्वे, आइसलैंड व लिस्टेनस्टिन), ब्रिटेन व ओमान के बाद अब न्यूजीलैंड ने एफटीए किया है। अगले महीने दो दर्जन से अधिक देश वाले यूरोपीय यूनियन (ईयू) के साथ भारत एफटीए कर सकता है। अगले साल अमेरिका व कनाडा जैसे बड़े देश के साथ भी एफटीए होने की पूरी उम्मीद है।

Dainik Jagaran Page No-10

समझौते में किसानों-उद्योगों के हितों का ध्यान रखा, सेब पर शुल्क छूट पाने वाला पहला देश बना न्यूजीलैंड

न्यूजीलैंड को डेयरी समेत कई संवेदनशील क्षेत्रों में छूट नहीं

व्यापार करार

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारत ने न्यूजीलैंड के साथ प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते में किसानों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों के हितों को प्राथमिकता दी है। इस कारण कुछ कृषि उत्पादों, डेयरी उत्पादों, कॉफी, मसाले, दालें और कुछ सब्जियों को समझौते से बाहर रखा है। इन क्षेत्रों में न्यूजीलैंड को कोई शुल्क रियायत नहीं दी जाएगी।

समझौते के तहत जिन उत्पादों को 'शुल्क रियायत सूची' से बाहर रखा गया है, उनमें डेयरी उत्पाद (दूध, क्रीम, दही, पनीर), पशु उत्पाद (भेड़ के मांस को छोड़कर), सब्जी उत्पाद (प्याज, चना, मटर, मक्का), चीनी, कृत्रिम शहद तथा पशु, वनस्पति या सूक्ष्मजीव आधारित वसा एवं तेल शामिल हैं।

इनके अलावा हथियार और गोला-बारूद, रत्न एवं आभूषण, तांबा और उससे बने उत्पाद और एल्युमिनियम एवं उससे संबंधित वस्तुओं पर भी भारत, न्यूजीलैंड को किसी तरह की शुल्क रियायत नहीं देगा।

न्यूजीलैंड किसी भी एफटीए के तहत अपने सेबों पर शुल्क में छूट पाने वाला 'पहला' देश बन गया है। वर्तमान में, भारत में सेबों पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगता है।

उत्पादन और 100% निर्यात की अनुमति होगी

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते के तहत न्यूजीलैंड की कंपनियां भारत में डेयरी का कच्चा माल या सामग्री लाकर उसमें से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बना सकती हैं और फिर उन सभी उत्पादों को पूरी तरह से विदेशों में बेच सकती हैं। इस व्यवस्था से भारत को न्यूजीलैंड और अन्य देशों को निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके लिए एक 'फास्टट्रैक' निवेश प्रक्रिया लागू की जाएगी, जो सिर्फ निर्यात के लिए उत्पाद बनाने वाले निवेश के लिए उपयोग होगी। डेयरी के लिए भारत ने कभी भी आयात शुल्क में छूट नहीं दी है और भविष्य में भी नीति में कोई बदलाव नहीं होगा।

भारत के लिए मायने

विशेषज्ञों के अनुसार, यह समझौता भारतीय कंपनियों को न्यूजीलैंड के साथ-साथ पूरे प्रशांत क्षेत्र में पहुंच देगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह समझौता ऐसे वक्त हो रहा है, जब व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत नए बाजार तलाश रहा है। मौजूदा चुनौतियों के बीच भारत की कोशिश दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल देशों के साथ व्यापार साझेदारी को बढ़ाने की है।

केवल महिला अधिकारी

खास बात यह है कि यह पहला ऐसा समझौता है, जिसमें वार्ता में शामिल भारतीय पक्ष के सभी प्रमुख अधिकारी महिलाएं थीं। भारत की मुख्य वार्ताकार मंत्रालय में संयुक्त सचिव पेटल ढिल्लों हैं। इस साल मार्च में लवसन की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच एफटीएफ पर वार्ता शुरू करने पर सहमति बनी थी। यह व्यापार वार्ता महज नौ महीनों में पूरी हो गई। इससे यह किसी देश के साथ भारत के सबसे तेज व्यापार समझौतों में से एक बन गया है।

छात्रों-पेशेवरों को राहत

जीलैंड में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के लिए अब कोई संख्या तय नहीं होगी। इसका मतलब है कि समझौते के तहत कोटा सिस्टम खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, भारतीय छात्र अब पढ़ाई के दौरान हर हफ्ते कम से कम 20 घंटे काम कर सकेंगे। स्नातक के बाद छात्रों को तीन-चार वर्ष तक न्यूजीलैंड काम करने का मौका मिलेगा। समझौते के तहत हर साल पांच हजार भारतीय पेशेवरों के लिए तीन साल के वर्क वीजा का रास्ता भी साफ हो गया है।

सात-आठ महीने में लागू होगा समझौता

न्यूजीलैंड के साथ एफटीए को लेकर चल रही वार्ता संपन्न होने के बाद भारत की तरफ से कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है लेकिन अभी न्यूजीलैंड में कानूनी प्रक्रिया के बाद वहां की संसद द्वारा मंजूर किया जाएगा। उसके बाद समझौते पर दोनों देश अंतिम रूप से हस्ताक्षर करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि मौजूदा समय से समझौते को लागू होने में सात से आठ महीने का वक्त लग सकता है।

सरकार ने नया मील का पत्थर स्थापित किया : शाह

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लोगों के हित में विदेश नीति का एक उदाहरण है।

उन्होंने इसे मोदी सरकार की व्यापार कूटनीति में एक नया मील का पत्थर बताया। उन्होंने 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे जन-केंद्रित विदेश नीति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा कर रही है। यह एफटीए बाजार पहुंच को बढ़ाएगा और निवेश प्रवाह को मजबूत करेगा।'

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जन हित में विदेश नीति का एक उदाहरण

शराब का शुल्क-मुक्त निर्यात

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत भारत से शराब और वाइन के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगेगा जबकि न्यूजीलैंड से आयातित वाइन पर रियायती शुल्क लगाए जाएंगे जिसे 10 साल में धीरे-धीरे घटाया जाएगा।

अंगूर से बनने वाली वाइन पर फिलहाल भारत में 150 प्रतिशत शुल्क लागू है। न्यूजीलैंड की वाइन पर यह शुल्क पहले दिन 100% हो जाएगा और 10वें वर्ष तक क्रमिक रूप से घटकर 50 प्रतिशत रह जाएगा। शुल्क की संरचना पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया के साथ दिसंबर, 2022 में लागू द्विपक्षीय व्यापार समझौते के समान ही है।

न्यूजीलैंड के वाणिज्य मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, एफटीए लागू होने के 10 वर्षों में न्यूजीलैंड वाइन पर 66-83 प्रतिशत तक शुल्क कटौती होगी।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचि
बिहार
बिहार सरका

Hindustan Page No-13

सहमतिः भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता पूरी, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की घोषणा

न्यूजीलैंड से व्यापार और रोजगार बढ़ाने का करार

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार और रोजगार बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर सोमवार को अंतिम सहमति बन गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने फोन पर बातचीत की, जिसके बाद समझौता वार्ता पूरी होने की घोषणा की गई।

समझौते के तहत न्यूजीलैंड अपने यहां भारत से आने वाले 100 फीसदी उत्पादों पर आयात शुल्क खत्म कर देगा। इससे भारतीय निर्यातकों, छात्रों और पेशेवरों को बड़े पैमाने पर फायदा मिलने की संभावना है।

अब तक सात देशों के साथ करारः वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि एनडीए सरकार के नेतृत्व में यह सातवां समझौता है, जिसे अंतिम रूप दिया गया है। इससे पहले यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ओमान, यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन, मॉरीशस के साथ ऐसे समझौते हो चुके हैं। फाइव आइज के तीन देशों संग भी एफटीए हुआ है। कई क्षेत्रों में छूट नहीं P13

नई दिल्ली में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। साथ में है वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल। • एएनआई

किसानों के हितों का रखा ख्याल

डेयरी उत्पादों, डेयरी से बनी चीजों और कॉफी, मसाले, दालें और कुछ सब्जियों को समझौते से बाहर रखा गया है, ताकि भारतीय किसानों को नुकसान न हो। हालांकि, न्यूजीलैंड से आने वाले सेब और वीवी जैसे फलों पर एक तय सीमा के तहत कम कर लगेगा।

मौजूदा व्यापार की स्थिति

वर्ष 2024 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 2.4 अरब डॉलर था। इसमें प्रमुख तौर पर यात्रा, आईटी और व्यावसायिक सेवाएं शामिल रहीं।

भारत को क्या मिलेगा

1 भारतीय निर्यात पर शून्य शुल्क
अब तक न्यूजीलैंड भारतीय निर्यात पर करीब 10% तक आयात शुल्क लगाता था, जो समझौता लागू होने के बाद शून्य हो जाएगा।

2 इन प्रमुख क्षेत्रों को राहत मिलेगी
वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, चमड़ा,इंजीनियरिंग वस्तुएं, कृषि उत्पाद, कंप्यूटर-संबंधित सेवाएं, पेशेवर सेवाएं, दूरसंचार आदि।

3 20 अरब डॉलर का 15 सालों में निवेश
न्यूजीलैंड 15 वर्षों में भारत के कृषि, डेयरी,टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, शिक्षा, स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में 20 अरब डॉलर निवेश करेगा।

4 भारतीय छात्रों को वीजा में छूट
भारतीय छात्रों को चार वर्ष तक का पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। हर हफ्ते कम 20 घंटे काम भी कर सकेंगे।

09 नौ माह में ही पूरी हुई वार्ता, यह सबसे तेज व्यापार समझौता

इनका अधिक निर्यात
विमानन टरबाइन ईंधन, वस्त्र, दवाएं, पेट्रोलियम उत्पाद, मोटर वाहन व उनके कलपुर्जे, कागज व पेपरबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक, इस्पात, बासमती चावल

क्या आयात होता है
कृषि संबंधी वस्तुएं,लकड़ी एवं लकड़ी से बने उत्पाद, कागज, एल्युमीनियम स्क्रैप, इस्पात एवं कई अन्य उत्पाद।

66 भारत-न्यूजीलैंड साझेदारी अब नई ऊंचाइयों को छूने जा रही है। दोनों देशों के संबंधों के लिए यह एक महत्वपूर्ण क्षण है।
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

66 यह समझौता दोनों देशों की मजबूत मित्रता पर आधारित है। इससे हमें 1.4 अरब भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंचने का मौका मिलता है।
-क्रिस्टोफर लक्सन, प्रधानमंत्री-न्यूजीलैंड

Hindustan Page No-5

गर्मी व आर्द्रता से बच्चों में बौनापन में होगी वृद्धि

अध्ययन ▶ 2050 तक जलवायु परिवर्तन से दक्षिण एशिया में 30 लाख से अधिक बच्चे होंगे प्रभावित

गर्भावस्था के दौरान अत्यधिक गर्म और आर्द्र परिस्थितियों का होता है नकारात्मक प्रभाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न गर्म और आर्द्र परिस्थितियों के चलते दक्षिण एशिया के बच्चों में बौनापन के मामलों में 2050 तक 30 लाख से अधिक की वृद्धि होने का अनुमान है। गर्भावस्था के दौरान और बचपन में अत्यधिक गर्म और आर्द्रता के संपर्क में आने से भ्रूण के विकास और बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जो तापमान अकेले से होने वाले प्रभाव से कहीं ज्यादा हानिकारक है।

यह स्थिति बच्चों के शारीरिक विकास, सीखने की क्षमता और भविष्य के अवसरों को प्रभावित करती है, जिससे स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव बढ़ता है। एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। यह अध्ययन अमेरिका के सांता बारबरा के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया।

प्रतीकात्मक

दक्षिण एशिया में सबसे घनी आबादी, तापमान वृद्धि और आर्द्रता का पड़ेगा असर

शोधकर्ताओं ने कहा कि गर्मी और आर्द्रता की परिस्थितियां निरंतर वैश्विक तापमान वृद्धि के तहत बढ़ने की संभावना है और दक्षिण एशिया को दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक माना जा रहा है। यह पृथ्वी के सबसे घनी आबादी वाले स्थान हैं। उन्होंने लिखा कि हम पाते हैं कि गर्म आर्द्र संपर्क स्वास्थ्य के लिए केवल गर्म तापमान की तुलना में कहीं अधिक हानिकारक हैं। टीम ने कहा कि इसलिए यदि शोधकर्ता, डाक्टर और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी केवल तापमान के प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो वे चरम मौसम के वास्तविक प्रभावों को कम आंक रहे हैं।

गर्मी और आर्द्रता के कारण चार गुना मामले ज्यादा प्रभावित : जर्नल साइंस में प्रकाशित निष्कर्षों से पता चलता है कि आंशिक रूप से आर्द्रता गर्मी के संपर्क के प्रभावों को बढ़ा सकती है क्योंकि यह गर्भवती महिलाओं को ठंडा होने से रोकती है। गर्भावस्था के प्रारंभ और अंत में सबसे खराब समय पाया गया। प्रमुख लेखिका कैटी मैकमैहन ने कहा कि गर्भावस्था के प्रारंभ में भ्रूण बहुत संवेदनशील होता है, जबकि गर्भावस्था के अंत में मां अधिक संवेदनशील होती है। गर्भवती को अतिरिक्त वजन और हार्मोनल बदलावों के कारण गर्मी के तनाव के प्रति संवेदनशील माना जाता है।

बढ़ती गर्मी और आर्द्रता ज्यादा खतरनाक : वेट बल्ब ग्लोब टेम्परेचर में हवा के तापमान के अलावा तीन अतिरिक्त कारकों को शामिल किया जाता है जो गर्मी के तनाव को प्रभावित करते हैं: आर्द्रता, विकिरण गर्मी और वायु प्रवाह। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि अधिकतम वेट-बल्ब ग्लोब टेम्परेचर 29 डिग्री से अधिक होने वाले प्रत्येक अतिरिक्त दिन का संबंध छह से 12 महीने बाद जीवित जन्मों की संख्या में कमी से था। हालांकि, 35 डिग्री से अधिक अधिकतम तापमान वाले प्रत्येक अतिरिक्त दिन का संबंध तीन महीने के संपर्क में जन्म दर में वृद्धि से पाया गया। शोधकर्ताओं ने कहा कि केवल गर्म तापमान की तुलना में गर्म, आर्द्र परिस्थितियों के संपर्क में आना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।

Dainik Jagaran Page No-14

रूस के एसयू-57 ने नए जेनरेशन के इंजन के साथ भरी पहली उड़ान

मास्को, प्रेट्र : रूस के पांचवीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर एसयू-57 ने नए इंजन के साथ अपनी पहली उड़ान भरी। सरकारी एयरोस्पेस कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कार्पोरेशन (यूएसी) ने सोमवार को यह जानकारी दी। कार्पोरेशन ने कहा कि सरकारी रोस्टेक ग्रुप की सहायक कंपनी यूनाइटेड इंजन कार्पोरेशन के सहयोग से एसयू-57 एयरक्राफ्ट सिस्टम के हिस्से के रूप में इजडेलिये 177 इंजन का फ्लाइट टेस्ट शुरू हो गया है।

एसयू-57 के लिए खास तौर पर विकसित यह एडवांस्ड इंजन अधिक थ्रस्ट और बेहतर फ्लाइट परफार्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस ने दावा किया है कि एसयू-57 एकमात्र युद्ध में आजमाया हुआ पांचवीं पीढ़ी का फाइटर है, और इसके लिए उसने सीरिया और यूक्रेन में इसके आपरेशनल इस्तेमाल का हवाला दिया है।

टेस्ट पायलट रोमन कोंड्रैटयेव ने विमान को उड़ाया। उड़ान प्लान के मुताबिक हुई और नए इंजन ने भरोसेमंद तरीके से काम किया। रोस्टेक के अनुसार इजडेलिये 177 इंजन विमान की उड़ान परफार्मेंस को बेहतर बनाएगा और आगे के विकास में मदद करेगा। यूएसी ने कहा कि वह रूसी सेना और एक्सपोर्ट कस्टमर्स को डिलीवरी बढ़ाने के लिए एसयू-57 का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है।

- इंजन अधिक थ्रस्ट व बेहतर परफार्मेंस देने के लिए डिजाइन किया गया है
- रूस का दावा, युद्ध में आजमाया हुआ एकमात्र विमान है एसयू-57

रूस में अपनी पहली उड़ाने के दौरान पांचवी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर एसयू-57। वीडियोग्रैब

Dainik Jagaran Page No-11

विश्व परिक्रमा

इजराइल : तेल अवीव विश्वविद्यालय में भारत पीठ की स्थापना

जनसत्ता संवाद

भारत-इजराइल रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आइसीसीआर) और तेल अवीव विश्वविद्यालय (टीएयू) के बीच सोमवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत इस शैक्षणिक संस्थान में 'भारत पीठ' की स्थापना की जाएगी।

इजराइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह और तेल अवीव विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर एरियल पोराट ने औपचारिक रूप से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे पहली बार टीएयू में 'भारत पीठ' की स्थापना होगी। सिंह ने भारत और इजराइल के बीच शैक्षणिक और अकादमिक सहयोग को और मजबूत करने के अवसरों पर

चर्चा करने के लिए विश्वविद्यालय के अध्यक्ष और विभिन्न संकायों के प्रमुखों के साथ भी बैठक की।

टीएयू की प्रवक्ता नोगा शाहर ने बताया, 'इजराइल में यह अपनी तरह की पहली पहल है। इस पहल से टीएयू को हर साल विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों के अग्रणी भारतीय छात्रों की मेजबानी करने में मदद मिलेगी।'

उन्होंने कहा कि 'भारत पीठ' के विजिटिंग प्रोफेसर टीएयू में पूरा सेमेस्टर बिताएंगे, पूरा अकादमिक पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे और व्याख्यान देंगे। टीएयू के प्रवक्ता ने कहा कि यह व्याख्यान भारत के समकालीन मुद्दों पर आधारित होंगे। 'एशिया एंगेजमेंट' के निदेशक कान्स्टेंटिन प्लाटोनोव ने बताया, 'टीएयू में आइसीसीआर-टीएयू 'भारत पीठ' की शुरुआत करके और स्थायी प्रतिनिधित्व के लिए दिल्ली में टीएयू 'इंडिया हब' की स्थापना करके, हम भारतीय छात्रों, अनुसंधान भागीदारों और अन्य हितधारकों के साथ अपने जुड़ाव को अगले स्तर पर ले जा रहे हैं।'

Jansatta Page No-7

शोध

आठ हजार प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा

जनसत्ता संवाद

जलवायु परिवर्तन के कारण जैव विविधता पर बुरा असर दिखने लगा है। एक वैश्विक अध्ययन के मुताबिक, सदी के अंत तक जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आवासों पर बढ़ते इंसानी दबाव के कारण करीब आठ हजार प्रजातियों की विलुप्ति का खतरा सामने आ खड़ा हुआ है। आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के अध्ययन में पाया गया है कि सदी के अंत तक बढ़ती गर्मी और भूमि उपयोग में बदलाव (मानव दबाव) से प्रजातियों के प्राकृतिक आवास प्रभावित होंगे।

जिन जंगलों, घास के मैदानों और दलदलों में हजारों वर्षों से जीवन फलता-फूलता आया है, वही अब जानलेवा बनते जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से बढ़ती गर्मी और जमीन पर बढ़ता इंसानी दबाव – इन दोनों ने मिलकर जीवों की हजारों प्रजातियों के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस बारे में अध्ययन आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के 'स्कूल आफ जियोग्राफी एंड द एनवायरमेंट' से जुड़े वैज्ञानिक डाक्टर रुत वर्दी के नेतृत्व में किया गया है। इस अध्ययन में इंडियन इंस्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलुरु से जुड़े शोधकर्ता गोपाल मुरली भी शामिल थे। इसके साथ ही अध्ययन में यूके, आस्ट्रेलिया और इजराइल से जुड़े शोधकर्ताओं ने भी अपना योगदान दिया है। अध्ययन के नतीजे अंतराष्ट्रीय जर्नल ग्लोबल चेंज बायोलाजी में प्रकाशित हुए हैं।

अपने इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों और सरीसृपों समेत जमीन पर पाई जाने वाली करीब 30,000 प्रजातियों का विश्लेषण किया है। अध्ययन में यह

आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के 'स्कूल आफ जियोग्राफी एंड द एनवायरमेंट' में शोधकर्ताओं ने उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों और सरीसृपों समेत जमीन पर पाई जाने वाली करीब 30,000 प्रजातियों का विश्लेषण किया है। अध्ययन में यह समझने का प्रयास किया गया है कि बढ़ती भीषण गर्मी और भूमि उपयोग में बदलाव, प्रजातियों पर कितना गहरा असर डालेंगे। अध्ययन के मुताबिक, सदी के अंत तक 7,895 प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं।

(फाइल फोटो)

से रहने योग्य नहीं रह जाएगा।

जलवायु परिवर्तन और भूमि उपयोग में बदलाव का संयुक्त असर साहेल, मध्य पूर्व और ब्राजील जैसे इलाकों में सबसे ज्यादा गंभीर होने का अंदेशा है। दो परिदृश्यों में तो यह तक सामने आया है कि कई प्रजातियों के लिए हालात बहुत खराब हो सकते हैं।

समझने का प्रयास किया गया है कि आने वाले समय में बढ़ती भीषण गर्मी और भूमि उपयोग में बदलाव, प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों और उनकी गर्मी सहने की क्षमता पर कितना गहरा असर डालेंगे।

शोधकर्ताओं के मुताबिक, अलग-अलग खतरों को अलग-अलग देखने के बजाय उन्हें एक साथ समझना बेहद जरूरी है। डाक्टर रुत वर्दी ने इस बारे में समझते हुए प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'जब कई संकट एक साथ काम करते हैं, तो उनका असर कहीं ज्यादा विनाशकारी होता है। ऐसे में जैव विविधता को भारी नुकसान से बचाने के लिए तुरंत संरक्षण और उत्सर्जन कम करने के लिए कदम जरूरी हैं।'

अध्ययन के मुताबिक, सदी के अंत तक 7,895 प्रजातियां ऐसी स्थिति में पहुंच सकती हैं, जहां उनके पूरे प्राकृतिक आवास क्षेत्र में या तो भीषण गर्मी होगी, या जमीन उनके रहने लायक नहीं बचेगी, या फिर दोनों संकट एक साथ उनपर हावी होंगे। ऐसी परिस्थितियां उन्हें विलुप्ति के खतरे में डाल सकती हैं।

यह भी सामने आया है कि भविष्य में जलवायु के चार अलग-अलग परिदृश्यों में सबसे गंभीर स्थिति यह दर्शाती है कि औसतन प्रजातियों के 52 फीसद आवास क्षेत्र रहने लायक नहीं रहेंगे। यहां तक कि सबसे आशावादी परिदृश्य में भी, औसतन 10 फीसद क्षेत्र जलवायु परिवर्तन और भूमि-उपयोग के संयुक्त असर

Jansatta Page No-7

खेल मंत्री ने साई संचालन समिति की अध्यक्षता की | बैठक | खिलाड़ियों के व्यापक विकास को बढ़ावा देना उद्देश्य

देश भर के केंद्रों में बुनियादी ढांचे के उन्नयन को मंजूरी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की संचालन समिति ने सोमवार को देश भर में कई अवसंरचना उन्नयन परियोजनाओं को मंजूरी दी जिनमें पश्चिम बंगाल में आठ लेन के सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक और बेंगलुरु केंद्र में 'क्लाइमेट न्यूट्रल (पर्यावरण के दुष्प्रभाव से रहित) हाकी टर्फ का निर्माण शामिल है।

खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने साइ (संचालन समिति) की इस बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस बैठक को संबोधित करते हुए कहा,' भारतीय खेल पारिस्थितिकी तंत्र अभी अपनी युवावस्था में है और भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए इसे हर संभव तरीके से मजबूत करना समय की मांग है।' उन्होंने कहा कि हम आज खिलाड़ी-केंद्रित निर्णय ले रहे हैं और इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खिलाड़ियों को सर्वोत्तम अवसंरचना मिले ताकि राष्ट्रमंडल खेलों और ओलंपिक जैसे बड़े आयोजनों में पदक जीतने के हमारे लक्ष्य को पूरा किया जा सके।' संचालन समिति द्वारा अनुशंसित प्रमुख परियोजनाओं में से एक साइ बंगलुरु के लिए

परियोजनाओं में पश्चिम बंगाल में आठ लेन के सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक और बंगलुरु केंद्र में ह्यक्लाइमेट न्यूट्रल (पर्यावरण के दुष्प्रभाव से रहित) हाकी टर्फ का निर्माण शामिल है।

संचालन समिति ने इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी केंद्र में 400 मीटर लंबे, आठ लेन वाले सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक के निर्माण के साथ भोपाल स्थित केंद्र में नई सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक लगाने की भी मंजूरी दी।

'पोलिग्रास पेरिस जीटी जीरो हाकी टर्फ' की खरीद है। यह स्थल पर भारतीय पुरुष और महिला राष्ट्रीय एवं 'ए' हाकी टीमों के प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करता है।'पोलिग्रास पेरिस जीटी जीरो हाकी टर्फ' को अंतरराष्ट्रीय हाकी महासंघ (एफआइएच) द्वारा प्रमाणित किया गया है और यह घर्षण और पानी की आवश्यकता को कम करने का दावा करता है। यह टर्फ अधिक पानी दिए बिना भी गेंद को लगातार लुढ़कने देता है, जिससे पानी जैसे अहम संसाधन की बचत होती है।

संचालन समिति ने करणी सिंह निशानेबाजी परिसर (केएसआर) में मौजूदा इलेक्ट्रानिक निशानेबाजी लक्ष्यों को लेजर लक्ष्य प्रणालियों से बदलने पर भी सहमति व्यक्त की। इस स्थल पर अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन होता है और यह शीर्ष अभ्यास केंद्र भी है। खेल मंत्रालय से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक कि संचालन समिति ने इसके अलावा ने साई एनसीओइ (राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र) छत्रपति संभाजीनगर, साइ पटियाला और साइ त्रिवेंद्रम में तीन बहुउद्देशीय हाल के निर्माण को भी मंजूरी दी, ताकि गहन प्रशिक्षण और खिलाड़ियों के व्यापक विकास को बढ़ावा दिया जा सके।

Jansatta Page No-22

पनडुब्बी रोधी पोत 'अंजदीप' नौसेना को सौंपा गया

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा)।

पनडुब्बी रोधी पोत 'अंजदीप' को सोमवार को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसइ), कोलकाता द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित आठ एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी (पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज) में से तीसरा पोत चेन्नई में नौसेना को सौंप दिया गया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी पोत को जीआरएसई और मेसर्स एल एंड टी शिपयार्ड, कट्टुपल्ली के सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) के तहत इंडियन रजिस्टर आफ शिपिंग (आइआरएस) के वर्गीकरण नियमों के अनुसार डिजाइन और निर्मित किया गया है। यह सहयोगी रक्षा विनिर्माण की सफलता को दर्शाता है। लगभग 77 मीटर लंबाई वाला यह जहाज भारतीय नौसेना का सबसे बड़े वाटरजेट पोत हैं और अत्याधुनिक हल्के टारपीडो, स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी रोधी राकेट और सोनार से सुसज्जित है।

जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी के विशेष दूत के रूप में श्रीलंका की यात्रा शुरू की

कोलंबो/नई दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा)।

चक्रवात डिटवा के बाद पुनर्निर्माण कार्य शुरू होने के उपलक्ष्य में विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को कोलंबो पहुंचे, जहां वे श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करेंगे। जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष दूत के रूप में श्रीलंका की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में कहा कि यह दौरा भारत की 'पड़ोसी प्रथम' नीति को रेखांकित करता है और चक्रवात डिटवा से हुई तबाही से निपटने के लिए शुरू किए गए आपरेशन सागरबंधु के संदर्भ में हो रहा है। नवंबर के अंत में द्वीपीय देश में आए चक्रवात ने 640 से अधिक लोगों की जान ले ली और फसलों, चाय बागानों और सड़कों और पुलों सहित महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया। भारत ने श्रीलंका को संकट से निपटने में मदद करने के लिए आपरेशन सागरबंधु शुरू किया था।

Jansatta Page No-12

नीति आयोग की रपट में हुआ खुलासा

उच्च शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा कनाडा जाते हैं भारतीय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

उच्च शिक्षा के लिए भारतीय विद्यार्थी सबसे ज्यादा कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया और जर्मनी जाते हैं। नीति आयोग की सोमवार को जारी एक रपट में यह कहा गया। भारत में उच्च शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण शीर्षक से जारी रपट में कहा गया है कि 2024 में, कनाडा 4,27,000 भारतीय विद्यार्थियों के साथ शीर्ष अंतरराष्ट्रीय उच्च शिक्षा गंतव्य था।

इसके बाद अमेरिका (3,37,630), ब्रिटेन (1,85,000) आस्ट्रेलिया (1,22,202) और जर्मनी (42,997) का स्थान रहा। इसमें कहा गया है कि भारत दुनिया में अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों का सबसे बड़ा स्रोत है। वर्ष 2024 में 13.35 लाख से अधिक विद्यार्थी विदेशों में अध्ययन कर रहे थे। रपट में कहा गया कि 2024 में भारत आने वाले प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी के मुकाबले 28 भारतीय विद्यार्थी विदेश गए, जो देश के लिए एक अहम प्रतिभा पलायन को दर्शाता है। रपट में भारत में विदेशी विद्यार्थियों के आगमन के बारे में 2021-22 के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि 2021-22 में नेपाल, अफगानिस्तान, अमेरिका, बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात भारत में अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के शीर्ष स्रोत देश थे।

> *रपट* में कहा गया कि 2024 में भारत आने वाले प्रत्येक एक अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी के मुकाबले 28 भारतीय विद्यार्थी विदेश गए।
>
> *इसमें* कहा गया है कि 2021-22 में नेपाल, अफगानिस्तान, अमेरिका, बांग्लादेश और संयुक्त अरब अमीरात भारत में अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों के शीर्ष स्रोत देश थे।

रपट के अनुसार कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया में 8.5 लाख भारतीय विद्यार्थी पढ़ते हैं। वहीं, लातविया में भारतीय विद्यार्थियों का फीसद सबसे अधिक 17.4 है। उसके बाद आयरलैंड में 15.3 फीसद और जर्मनी में 10.1 फीसद है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार राज्यों में आंध्र प्रदेश से सबसे ज्यादा 35,614 विद्यार्थी विदेश गए। उसके बाद पंजाब और महाराष्ट्र का स्थान रहा जहां से क्रमशः 33,412 और 29,079 विद्यार्थी विदेश गए। भारतीय रिजर्व बैंक की विदेश में पढ़ने वाले भारतीय के लिए उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत 2014-24 के दौरान संबंधित देशों को भेजी गई राशि 975 करोड़ रुपए से बढ़कर 29,000 करोड़ रुपए हो गई।

Jansatta Page No-12

वन भूमि अतिक्रमण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा | **टिप्पणी** | हजारों एकड़ वन भूमि को योजनाबद्ध तरीके से हड़पा गया

उत्तराखंड सरकार मूकदर्शक की तरह बैठी है

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले में सोमवार को उत्तराखंड सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि राज्य सरकार और उसके अधिकारी 'मूकदर्शक' की तरह बैठे रहे और अदालत ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची की अवकाश पीठ ने इस मामले को गंभीर मानते हुए सोमवार को इसकी परिधि बढ़ाकर स्वतः संज्ञान के रूप में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।

सुनवाई के दौरान पीठ ने प्रथम दृष्टया यह टिप्पणी की कि हजारों एकड़ वन भूमि को निजी व्यक्तियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से हड़पा गया। जबकि राज्य प्रशासन और वन विभाग ने इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। अदालत ने कहा कि रेकार्ड से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वन भूमि पर कब्जे की यह प्रक्रिया वर्षों तक चलती रही, लेकिन उत्तराखंड सरकार और उसके संबंधित अधिकारी इसे रोकने में पूरी तरह विफल रहे। इस स्थिति को चौंकाने वाला बताते हुए पीठ ने कहा कि राज्य मशीनरी की निष्क्रियता ने अवैध कब्जों को बढ़ावा दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव और प्रधान मुख्य वन संरक्षक को निर्देश दिया कि वे एक जांच समिति गठित करें, जो इस पूरे मामले से जुड़े सभी तथ्यों की जांच कर विस्तृत रपट अदालत के समक्ष प्रस्तुत करे। सुप्रीम कोर्ट अनिता कंडवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह कदम उठाया। याचिका में कहा गया है कि राज्य में वन भूमि के बड़े हिस्से पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। अंतरिम राहत के रूप में अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया कि विवादित भूमि से संबंधित किसी भी निजी व्यक्ति या संस्था को भूमि का हस्तांतरण, गिरवी रखना या किसी भी प्रकार के तृतीय-पक्ष अधिकार बनाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि संबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का नया निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। आवासीय मकानों को छोड़कर शेष सभी खाली भूमि का कब्जा तुरंत वन विभाग और संबंधित जिलाधिकारी द्वारा लिया जाए, ताकि वन भूमि की स्थिति को सुरक्षित रखा जा सके। यह विवाद लगभग 2866 एकड़ भूमि से संबंधित है। जिसे पहले सरकारी वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया था। आरोप है कि इस भूमि का एक हिस्सा ऋषिकेश स्थित एक संस्था पशु लोक सेवा समिति को लीज पर दिया गया था। बाद में समिति द्वारा कथित रूप से इस भूमि के अलग-अलग हिस्से अपने सदस्यों को आबंटित कर दिए गए। रेकार्ड के अनुसार, समिति और उसके सदस्यों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। जिसके परिणामस्वरूप एक संदिग्ध और मिलीभगतपूर्ण समझौता डिक्री पारित की गई। इसके पश्चात समिति के परिसमापन के दौरान 23 अक्टूबर 1984 को एक सरेंडर डीड के माध्यम से लगभग 594 एकड़ भूमि वन विभाग को वापस सौंप दी गई। यह आदेश अंतिम रूप से प्रभावी हो गया था।

> *प्रधान* न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जायमाल्य बागची की अवकाश पीठ ने इस मामले को गंभीर मानते हुए सोमवार को इसकी परिधि बढ़ाकर स्वतः संज्ञान के रूप में आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। सुनवाई के दौरान पीठ ने प्रथम दृष्टया यह टिप्पणी की कि हजारों एकड़ वन भूमि को निजी व्यक्तियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से हड़पा गया। जबकि राज्य प्रशासन और वन विभाग ने इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। अदालत ने कहा कि रेकार्ड से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वन भूमि पर कब्जे की यह प्रक्रिया वर्षों तक चलती रही, लेकिन उत्तराखंड सरकार और उसके संबंधित अधिकारी इसे रोकने में पूरी तरह विफल रहे।

Jansatta Page No-10

खनन माफिया निगल गए जीवनदायिनी अरावली के 31 पहाड़

- गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह एवं पलवल में अवैध खनन के बारे में आती रहती हैं शिकायतें
- पहाड़ों का अस्तित्व खत्म होने से ही राजस्थान से धूल भरी हवाएं अधिक चलने लगी हैं

आदित्य राज ● जागरण

गुरुग्राम : दिल्ली सहित पूरे एनसीआर के लिए जीवनदायिनी बनी अरावली के 31 पहाड़ खनन माफिया अब तक निगल चुके हैं। कई पहाड़ खत्म होने की कगार पर हैं। ऐसे में राजस्थान का मरुस्थल दिल्ली तक पहुंच जाएगा। फिर एनसीआर में लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर दिन-प्रतिदिन बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण अरावली का क्षरण है। पर्यावरणविदों का मानना है कि अरावली की सुरक्षा ही दिल्ली सहित एनसीआर की सुरक्षा है।

अरावली पहाड़ी क्षेत्र में वर्ष 1970 तक बाघ भी दिखाई देते थे। धीरे-धीरे भूमाफिया एवं खनन माफिया इलाके में इस तरह कदर सक्रिय हुए कि न केवल पहाड़, बल्कि बाघ सहित कई वन्यजीव गायब हो गए। अब गिनती के तेंदुआ, हिरण, नीलगाय एवं खरगोश सहित कुछ प्रकार के वन्यजीव बच गए हैं। होडल के नजदीक अरावली की वादियों का आनंद लेने के लिए लोग पहुंचते थे। वह गायब हो चुकी है। नारनौल जिले के नांगल दरगु के नजदीक कई पहाड़ गायब हो चुके हैं। गुरुग्राम में सोहना से आगे तीन से चार पहाड़ों का नामोनिशान नहीं। इसी तरह महेंद्रगढ़ के ख्वासपुर में पहाड़ लगभग गायब हो चुके हैं। नूंह इलाके का तो सबसे बुरा हाल है। तावडू के आसपास कई पहाड़ खत्म हो चुके हैं। राजस्थान से सटे इलाके के कई पहाड़ खत्म होने की कगार पर हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि जिस गति से पहाड़ खत्म होते जा रहे हैं, वैसे में कुछ ही सालों के भीतर राजस्थान का मरुस्थल दिल्ली के नजदीक होगा।

खनन की वजह से पहाड़ के नजदीक गायब हो चुकी हरियाली। जागरण

मैं गुरुग्राम जिले के गांव खांडसा का रहने वाला हूं। मैंने अरावली की खूबसूरती भी देखी है और धीरे-धीरे बर्बाद होते देख रहा हूं। खनन की वजह से सभी खत्म हो गए। अरावली का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि इसकी वजह से ही दिल्ली सहित पूरे एनसीआर के लोग सांस ले पा रहे हैं।
- राज चौहान, फिल्म अभिनेता

अरावली नहीं बची तो जीवन भी नहीं बचेगा। जीवनदायिनी अरावली के साथ गलत हो रहा है। भूमाफिया एवं खनन माफिया की वर्षों से नजर है। रोक के बाद भी कई इलाकों में खनन जारी है। अरावली पहाड़ी क्षेत्र में गैर वानिकी कार्यों पर रोक नहीं लगा पाना प्रशासन की विफलता है।
- वैशाली राणा, पर्यावरण कार्यकर्ता

प्रतिबंध लगने के बाद खनन माफिया ने बदल दिया तरीका

खनन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद माफिया ने तरीका बदल दिया। अब इलाके में जब शादी समारोह या ऐसा फंक्शन रहता है, जिसमें जमकर आतिशबाजी की जाती है, उस दौरान पहाड़ में ब्लास्ट किया जाता है। इससे लोगों को शक नहीं होता। बाद में मौका मिलते ही डंपर या ट्रैक्टर से पत्थर उठाकर ले माफिया के लोग ले जाते हैं। एक तरीका और इजाद किया है। पहाड़ पर उस जगह चोट मारा जाता है जहां से पत्थर आसानी से गिर जाएं। पहाड़ों में चोट मारकर खनन करने के तरीके का गुरुग्राम एवं फरीदबाद के इलाके में अधिक प्रयोग किया जाता है। खनन माफिया के मुखबिर पहाड़ों की ऊंचाई पर ही नहीं बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों के रास्ते की शुरुआत में बैठे रहते हैं। जैसे ही वन या खनन विभाग की गाड़ी इलाके में पहुंचती है, सूचना दे दी जाती है। पकड़े जाने की नौबत आने पर वन, खनन या पुलिस विभाग की टीम पर हमला बोल देते हैं। तीन साल पहले तावडू इलाके में एक डीएसपी को सरेआम कुचलकर हत्या कर दी गई थी।

Dainik Jagaran Page No-2

आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर नवंबर में घटकर 1.8% पर

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा)।

देश के आठ प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर नवंबर में घटकर 1.8 फीसद रह गई। यह पिछले साल इसी महीने में 5.8 फीसद थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पादों और बिजली उत्पादन में गिरावट से यह नरमी आई है।

हालांकि, आंकड़ों से पता चलता है कि इन क्षेत्रों का प्रदर्शन मासिक आधार पर सुधरा है। अक्तूबर में आठ प्रमुख उद्योगों कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, बिजली, उर्वरक और इस्पात के उत्पादन में 0.1 फीसद की गिरावट आई। चालू वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-नवंबर अवधि में इन क्षेत्रों का उत्पादन 2.4 फीसद बढ़ा जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की समान अवधि में वृद्धि दर 4.4 फीसद रही थी। नवंबर में कोयला और इस्पात उत्पादन की वृद्धि दर में नरमी आई। हालांकि, उर्वरक और सीमेंट उत्पादन क्रमशः 5.6 फीसद और 14.5 फीसद बढ़ा।

इक्रा लि. की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि त्योहारों के बाद नवंबर 2025 में प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि अपेक्षित रूप से सुधरी, लेकिन यह अब भी सुस्त बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अक्तूबर और नवंबर के बीच वृद्धि में सुधार की अगुवाई अधिकांश क्षेत्रों ने की, जिसमें विशेष रूप से सीमेंट में तेज उछाल देखा गया। नायर ने कहा कि बुनियादी उद्योग की वृद्धि और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों को देखते हुए नवंबर 2025 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) के 3.5 से 4.5 फीसद तक बढ़ने की उम्मीद है।

Jansatta Page No-10

नव वर्ष में बदलेगा महंगाई, जीडीपी मापने का पैमाना

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा)।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि वह खुदरा मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय लेखा और औद्योगिक उत्पादन से जुड़े प्रमुख व्यापक आर्थिक आंकड़ों की नई शृंखला अगले वर्ष जारी करेगा, जिसमें आधार वर्ष बदला गया होगा। प्रमुख आर्थिक आंकड़ों की नई शृंखला के लिए आधार वर्ष बदलेगा।

मंत्रालय ने बयान में कहा कि वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति और राष्ट्रीय लेखा से संबंधित नई शृंखला को फरवरी, 2026 में जारी करेगा जबकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) की नई शृंखला मई, 2026 में जारी की जाएगी। आधिकारिक बयान के मुताबिक, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) के आधार वर्ष में बदलाव को लेकर मंगलवार को एक परामर्श कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इसके पहले मुंबई में 26 नवंबर को पहली कार्यशाला आयोजित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि खुदरा मुद्रास्फीति की नई शृंखला का आधार वर्ष 2024 होगा और इसे 12 फरवरी, 2026 को जारी किया जाएगा।

वहीं, राष्ट्रीय लेखा से जुड़े आंकड़े वित्त वर्ष 2022-23 को आधार वर्ष मानते हुए 27 फरवरी, 2026 को जारी किए जाएंगे। इसके अलावा, आईआईपी की नई शृंखला का आधार वर्ष भी 2022-23 होगा जिसे 28 मई, 2026 को जारी किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि आधार वर्ष में बदलाव पर होने वाली परामर्श कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जीडीपी, सीपीआइ और आइआइपी के आधार वर्ष संशोधन के तहत प्रस्तावित पद्धतिगत और संरचनात्मक बदलावों को साझा करना और प्रतिभागियों से सुझाव एवं टिप्पणियां प्राप्त करना है।

कार्यशाला में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों, वित्तीय संस्थानों और बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों, मामले के जानकार, प्रमुख सांख्यिकीय आंकड़ों के उपयोगकर्ताओं और केंद्र एवं राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों की भागीदारी होगी।

मंत्रालय ने बयान में कहा कि वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति और राष्ट्रीय लेखा से संबंधित नई शृंखला को फरवरी, 2026 में जारी करेगा जबकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की नई शृंखला मई, 2026 में जारी की जाएगी। आधिकारिक बयान के मुताबिक, सकल घरेलू उत्पाद, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार वर्ष में बदलाव को लेकर मंगलवार को एक परामर्श कार्यशाला आयोजित की जाएगी।

Jansatta Page No-10

व्यक्तित्व

कविता चंद : अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा

जनसत्ता संवाद

उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले की रहने वाली 40 साल की पर्वतारोही कविता चंद ने भारत का नाम रोशन किया है। उन्होंने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर तिरंगा फहराया है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4,892 मीटर है।

कविता चंद मूल रूप से अल्मोड़ा जिले के धारा नौला की रहने वाली हैं। वर्तमान में वे मुंबई में रह रही हैं। कविता चंद एंड्योरेंस एथलीट हैं। उन्होंने 12 दिसंबर 2025 को माउंट विंसन के शिखर तक चढ़ाई की थी। उत्तराखंड के सुदूर दुर्गम गांव से निकलकर दुनिया की सबसे दुर्गम चोटियों तक पहुंचने के उनके इस सफर को गर्व के साथ सराहा जा रहा है। वे कहती हैं, 'माउंट विंसन के शिखर पर भारतीय तिरंगा लहराना शब्दों से परे अहसास है। मैं उम्मीद करती हूं कि यह उपलब्धि पेशेवरों को यह विश्वास दिलाएगी कि फिटनेस, महत्त्वाकांक्षा और करिअर की सफलता एक साथ आगे बढ़ सकती हैं।' अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर फतह करना कविता के 'सेवन समिट्स' लक्ष्य की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। इस अभियान के तहत दुनिया के सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया जाता है। इससे पहले उन्होंने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस को भी फतह किया था। दुनिया की सबसे मुश्किल चोटियों में एक माउंट विंसन अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई करीब 4892 मीटर (16,050 फीट) है। 'सेवन समिट्स' (सभी सात महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां) में से एक है, जहां पर तापमान करीब -50 डिग्री तक चला जाता है।

कविता का माउंट विंसन का सफर तीन दिसंबर को शुरू हुआ था। तीन दिसंबर को कविता भारत से रवाना हुई थीं और चार दिसंबर को चिली के पुंटा एरेनास पहुंचीं। इसके बाद कविता ने सात दिसंबर दोपहर को यूनियन ग्लेशियर से आगे के लिए उड़ान भरी। सात दिसंबर को ही कविता लगभग 2,100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विंसन बेस कैंप पहुंचीं। कविता ने यूनियन ग्लेशियर से बेस कैंप तक का अंतिम सफर स्की-डिजाइन छोटे विमान से लगभग 40 मिनट में पूरा किया गया, जो अंटार्कटिका अभियानों से जुड़ी जटिल लाजिस्टिक्स को दिखाता है। इस अभियान का नेतृत्व प्रसिद्ध हाई-एल्टीट्यूड गाइड मिंग्मा डेविड शेरपा ने किया। भारतीय दल को अनुभवी पर्वतारोही भरत थम्मिनेनी और उनकी एक्सपेडिशन कंपनी 'बूट्स एंड क्रैम्पनट' सहयोग रहा। इन्हीं के मार्गदर्शन में नौ सदस्यीय भारतीय टीम ने शिखर तक सफलतापूर्वक पहुंच बनाई, जहां सावधानीपूर्वक प्लानिंग, समुचित समन्वय ने अति-प्रतिकूल अंटार्कटिक परिस्थितियों से निपटने में निर्णायक भूमिका निभाई।

बांग्लादेश में हिंसा व भारत से तनावपूर्ण संबंधों के लिए यूनुस जिम्मेदार : हसीना

नई दिल्ली, एएनआइ : हिंसा की आग में जल रहे बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने मो. यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर चरमपंथी तत्वों को बढ़ावा देने, भारत विरोधी भावनाएं भड़काने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध गहरे तथा मौलिक हैं और इस अंतरिम सरकार के चले जाने के बाद भी लंबे समय तक बने रहेंगे। यूनुस की शह पर चरमपंथियों द्वारा भारत के खिलाफ शत्रुता पैदा की जा रही है। बांग्लादेश में हिंसा एवं अराजकता बढ़ने और भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों के लिए वही जिम्मेदार हैं। धार्मिक उन्माद एवं हिंसा रोकने में अंतरिम सरकार पूरी तरह विफल रही है। यूनुस के पास बांग्लादेश की विदेश नीति को फिर से व्यवस्थित करने का कोई जनादेश नहीं है।

एक वर्चुअल साक्षात्कार में शेख हसीना ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हालिया तनाव जानबूझकर पैदा किया गया। ये घटनाक्रम घरेलू स्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा दोनों को खतरे में डालते हैं। मौजूदा हालात में अपने राजनयिकों एवं अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताएं जायज हैं। भारत दशकों से बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद मित्र और साझेदार रहा है। भारत के खिलाफ बढ़ती शत्रुता उन चरमपंथियों द्वारा निर्मित की जा रही है जिन्हें यूनुस शासन द्वारा प्रोत्साहित किया गया है।

फरवरी में होने वाले चुनावों पर हसीना ने कहा कि उनकी पार्टी अवामी लीग के बिना कोई भी चुनाव, चुनाव नहीं बल्कि एक 'राज्याभिषेक' होगा क्योंकि अवामी लीग को आगामी चुनावों में भाग लेने से रोक दिया गया है। मो. यूनुस बिना बांग्लादेशी जनता के एक भी वोट के शासन कर रहे हैं और अब वह उस पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे जनता ने नौ बार जनादेश देकर चुना है। हसीना ने चेतावनी दी कि एक अनिर्वाचित प्रशासन द्वारा लिए गए रणनीतिक निर्णयों के देश के लिए दीर्घकालिक परिणाम हो सकते हैं।

- **कहा, हमारी पार्टी अवामी लीग के बिना कोई भी चुनाव, चुनाव नहीं बल्कि राज्याभिषेक होगा**
- **'धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकामी और हादी की हत्या अराजकता का प्रतिबिंब'**

शेख हसीना। फाइल

भारत दशकों से बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद मित्र और भागीदार रहा है। हमारे राष्ट्रों के बीच संबंध गहरे और मौलिक हैं और इस अस्थायी अंतरिम सरकार के चले जाने के बाद भी लंबे समय तक बने रहेंगे। मुझे विश्वास है कि एक बार वैध शासन बहाल होने के बाद बांग्लादेश उस विवेकपूर्ण साझेदारी में वापस आ जाएगा जो हमने विगत 15 वर्षों में विकसित की है। – **शेख हसीना, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री**

हसीना ने यूनुस सरकार पर भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण बयान जारी करने और धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया। कहा, "उस्मान हादी की हत्या मौजूदा अंतरिम सरकार के तहत अराजकता का प्रतिबिंब है। यह दुखद हत्या उस अराजकता को दर्शाती है जिसने मेरी सरकार को उखाड़ फेंका और जो यूनुस शासन के तहत कई गुना बढ़ गई। हिंसा आम बात हो गई है, जबकि अंतरिम सरकार या तो इससे इन्कार करती है या इसे रोकने में नाकाम है। जब आप अपनी सीमाओं के भीतर बुनियादी व्यवस्था बनाए नहीं रख सकते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर आपकी विश्वसनीयता गिर जाती है। यह वास्तविकता है।'

'मेरी राजनीतिक हत्या करने को वापसी की मांग नहीं कर सकते'

हसीना ने अपने खिलाफ चल रही कानूनी कार्यवाही के बीच वापस देश लौटने की मांग को खारिज कर दिया और कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई राजनीति से प्रेरित थी। कहा, वह वर्तमान हालात में वापस नहीं जाएंगी। "मेरी राजनीतिक हत्या का सामना करने के लिए आप मेरी वापसी की मांग नहीं कर सकते।" मैंने मो. यूनुस को मामले को हेग में ले जाने की चुनौती दी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एक स्वतंत्र अदालत उन्हें बरी कर देगी। कहा, वह तभी वापस आएंगी जब बांग्लादेश में वैध सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका होगी।

Dainik Jagaran Page No-11

उद्योग जगत भारत-न्यूजीलैंड व्यापार समझौते से खुश, कहा

द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद

नई दिल्ली, 22 दिसंबर (भाषा)।

उद्योग जगत ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता संपन्न होने का स्वागत करते हुए सोमवार को कहा कि प्रस्तावित समझौते से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने और दोनों देशों की कंपनियों के लिए विकास के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

यह समझौता घरेलू वस्तुओं विशेष रूप से श्रम-प्रधान क्षेत्रों से आने वाली वस्तुओं को शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करेगा और इसमें 15 वर्षों में 20 अरब अमेरिकी डालर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) की प्रतिबद्धता शामिल है। इससे पांच वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना पांच अरब अमेरिकी डालर तक पहुंचने की उम्मीद है। उद्योग मंडल फिक्की के अध्यक्ष अनंत गोयनका ने कहा, 'भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते का स्वागत है। यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक जुड़ाव को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौते से द्विपक्षीय व्यापार, निवेश प्रवाह और सहयोग में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों की कंपनियों के लिए विकास के नए अवसर सृजित होंगे।'

प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ेगी : फियो अध्यक्ष

निर्यातकों के शीर्ष निकाय फियो ने सोमवार को कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता वहां के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाएगा और रोजगार सृजित करने वाले क्षेत्रों को गति देगा। भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए बातचीत पूरी होने की सोमवार को घोषणा की। यह समझौता श्रम-गहन क्षेत्रों से आने वाले विभिन्न घरेलू उत्पादों को शुल्क-मुक्त पहुंच देगा।

Jansatta Page No-10

स्मरण

सच साबित होती श्रद्धानंद की चेतावनी

बांग्लादेश में हाल ही में एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीटकर हत्या कर दी गई। यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि यह उस संघर्ष की अभिव्यक्ति है, जिसकी आशंका स्वामी श्रद्धानंद ने लगभग एक सदी पहले व्यक्त की थी

विनय आर्य
महासचिव, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा

आज बांग्लादेश में जिस अचानक भड़की हिंसा को हम पड़ोसी देश की आंतरिक समस्या बताकर टाल देना चाहते हैं, उसे स्वामी श्रद्धानंद ने अपने समय में एक ऐतिहासिक चेतावनी के रूप में पहचाना था। यही कारण है कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हिंदू समाज को भीतर से संगठित करने, सामाजिक रूप से सशक्त बनाने और आत्मसम्मान के साथ खड़ा करने में समर्पित कर दिया। स्वामी श्रद्धानंद की दृष्टि में हिंदू समाज का सबसे बड़ा संकट बाहरी आक्रमण नहीं था, बल्कि आंतरिक विघटन था। जाति-भेद, छुआछूत, ऊंच-नीच और सामाजिक अलगाव ने समाज को इस कदर कमजोर कर दिया था कि संकट के समय वह अपने ही लोगों की रक्षा करने में असमर्थ होता जा रहा था। वह मानते थे कि जब तक समाज अपने सबसे कमजोर वर्गों, पिछड़ों और बेटियों को साथ लेकर नहीं चलेगा, तब तक धर्म केवल पूजा-पद्धति बनकर रह जाएगा, सुरक्षा कवच नहीं बन पाएगा।

आज बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को देखकर शोक व्यक्त करना आसान है, परंतु असली सवाल यह है कि क्या हमने उस चेतावनी से कुछ सीखा? क्या हमने अपने समाज को इतना संगठित, समावेशी और आत्मविश्वासी बनाया है कि वह किसी भी चुनौती का सामना एकजुट होकर कर सके? स्वामी श्रद्धानंद का जीवन इसी प्रश्न का व्यावहारिक उत्तर था। उन्होंने स्पष्ट देखा कि हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग सदियों से हाशिये पर धकेल दिया गया था। जो समाज अपने ही लोगों को अस्पृश्य मानता हो, उनके साथ रहने-बैठने से कतराता हो, वह समाज बाहरी आक्रामकता का सामना कैसे करेगा?

इसी बोध से प्रेरित होकर उन्होंने आर्य समाज को केवल धार्मिक आंदोलन नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार का सशक्त माध्यम बनाया। उनका लक्ष्य था सनातन समाज को भीतर से जोड़ना, न कि केवल बाहरी खतरों का शोर मचाना। इसी सोच का मूर्त रूप थीं आर्यनगर नाम की कालोनियां। उत्तर भारत के कई शहरों और कस्बों में आर्य समाज से जुड़े कार्यकर्ताओं ने स्वामी श्रद्धानंद के मार्गदर्शन में ये कालोनियां बसाईं। आर्यनगर एक सामाजिक पुनर्निर्माण का प्रयोग था। यहां उन लोगों को बसाया गया जिन्हें सदियों से गांवों और शहरों की मुख्यधारा से दूर रखा गया था। उद्देश्य स्पष्ट था उन्हें सम्मानजनक आवास, शिक्षा, धार्मिक स्थान और बुनियादी सुविधाएं देकर समाज के केंद्र में लाना।

आर्यनगरों में मंदिर बनाए गए, लेकिन वे केवल पूजा के स्थान नहीं थे। वे सामाजिक समरसता के केंद्र थे, जहां सभी जातियों के लोग एक साथ बैठते, सीखते और जुड़ते थे। विद्यालय और पुस्तकालय स्थापित किए गए, ताकि अगली पीढ़ी अज्ञान और हीनता की बेड़ियों से मुक्त हो सके। स्वामी श्रद्धानंद का विश्वास था कि शिक्षा ही वह आधार है, जिस पर आत्मसम्मान और संगठन खड़ा होता है। यही कारण है कि इन बस्तियों से बड़ी संख्या में शिक्षक, समाजसेवी और जागरूक नागरिक निकले, जिन्होंने आगे चलकर समाज को दिशा दी।

कमजोर पड़ते मानवीय संबंध : आज का भारत भले ही शहरीकरण, डिजिटल क्रांति और आर्थिक विकास की बात करता हो, लेकिन सामाजिक स्तर पर वही पुराने प्रश्न नए रूप में खड़े हैं। ऊंची इमारतों के बीच झुग्गियां हैं, स्मार्ट सिटी के बीच सामाजिक दूरी है और आनलाइन जुड़ाव के बावजूद मानवीय संबंध कमजोर पड़े हैं। हम इंटरनेट मीडिया पर धर्म को लेकर आक्रामक हो जाते हैं, लेकिन जमीन पर समाज को जोड़ने का धैर्य एवं संकल्प नहीं दिखता। स्वामी श्रद्धानंद का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि धर्म की रक्षा नारों से नहीं, सामाजिक संरचना से होती है। उनका बलिदान इसी संरचना-निर्माण की कीमत था। वह न तो अंधी कट्टरता के पक्षधर थे और न ही कायर आत्मसमर्पण के। वह संवाद चाहते थे, लेकिन आत्मगौरव के साथ।

आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरें आती हैं, तो स्वामी श्रद्धानंद की चेतावनी और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। यदि समाज भीतर से संगठित नहीं होगा, यदि दलित-पिछड़े-गरीब को साथ लेकर चलने की ईमानदार कोशिश नहीं होगी, तो बाहरी क्रूरता बार-बार हमें चोट पहुंचाती रहेगी। आर्यनगर जैसे प्रयोग आज भी हमारे लिए माडल हैं, जहां विकास का अर्थ केवल सड़क और मकान नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और सामूहिकता है।

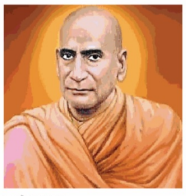

स्वामी श्रद्धानंद।

स्वामी श्रद्धानंद की सच्ची विरासत यही है एक ऐसा समाज, जो जातियों में बंटा न हो, बल्कि नागरिकता, संस्कार और आत्मसम्मान में एक हो। उनका स्मरण तभी सार्थक होगा, जब हम उनके विचारों को आज के यथार्थ में उतारने का साहस दिखाएं। आज उनकी पुण्य तिथि है। ऐसे में आज यदि हम यह साहस कर पाए तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

Dainik Jagaran Page No-9

खुदरा मुद्रास्फीति और जीडीपी की गणना में होगा बड़ा बदलाव

नई दिल्ली, एजेंसी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि देश के प्रमुख व्यापक आर्थिक संकेतकों—खुदरा मुद्रास्फीति, जीडीपी और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की नई शृंखलाएं अगले वर्ष जारी की जाएंगी, जिनमें इनके आधार वर्ष बदले जाएंगे।

सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति और राष्ट्रीय लेखा से संबंधित संशोधित आंकड़े फरवरी 2026 में जारी किए जाएंगे, जबकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की नई शृंखला मई 2026 में प्रकाशित होगी।

आधिकारिक बयान में बताया गया कि जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के आधार वर्ष में बदलाव को लेकर मंगलवार को एक परामर्श कार्यशाला आयोजित की जाएगी। इससे पहले इसी विषय पर 26 नवंबर को मुंबई में पहली कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि खुदरा मुद्रास्फीति की नई शृंखला के लिए आधार वर्ष 2024 तय किया गया है और इसे 12 फरवरी 2026 को जारी किया जाएगा।

वहीं, राष्ट्रीय लेखा से जुड़े आंकड़ों के लिए वित्त वर्ष 2022-23 को आधार वर्ष माना जाएगा और यह नई शृंखला 27 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी।

इसके अलावा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) की नई शृंखला का आधार वर्ष भी 2022-2023 होगा, जिसे 28 मई 2026 को जारी करने की योजना है।

आम आदमी को क्या फायदा होगा?

■ **आधार वर्ष क्या होता है और इसे क्यों बदला जाता है?**
आधार वर्ष वह साल होता है, जिसके मुकाबले महंगाई, उत्पादन और आर्थिक वृद्धि को मापा जाता है। समय के साथ लोगों की खर्च करने की आदतें, तकनीक और बाजार बदल जाते हैं। इसलिए पुराने आधार वर्ष से सही तस्वीर नहीं मिलती, इसी वजह से इसे बदला जाता है।

■ **खुदरा महंगाई का आधार वर्ष बदलने से क्या बदलेगा?**
नई शृंखला में आज के खर्च—जैसे मोबाइल, इंटरनेट, स्वास्थ्य और शिक्षा—को ज्यादा महत्व मिलेगा। इससे महंगाई का आंकड़ा आम आदमी के रोजमर्रा के खर्च के ज्यादा करीब होगा।

■ **क्या इससे महंगाई अचानक बढ़ या घट जाएगी?**
नहीं। आधार वर्ष बदलने से महंगाई की वास्तविक दर नहीं बदलती, बल्कि उसकी गणना ज्यादा सटीक हो जाती है। आंकड़ों में बदलाव दिख सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कीमतें रातों-रात बदल जाएंगी।

■ **क्या इसका असर वेतन, पेंशन और महंगाई भत्ते पर पड़ेगा?**
हां, अप्रत्यक्ष रूप से। महंगाई भत्ता, पेंशन और कई मजदूरी दरें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़ी होती हैं। अधिक सटीक सीपीआई से ये बढ़ोतरी ज्यादा न्यायसंगत और वास्तविक हो सकती है।

■ **मासिक किस्त और ब्याज दरों पर इसका क्या असर होगा?**
आरबीआई महंगाई और जीडीपी के आंकड़ों के आधार पर ब्याज दरों पर फैसला करता है। बेहतर और भरोसेमंद आंकड़ों से होम लोन और अन्य मासिक किस्तों से जुड़े फैसले संतुलित हो सकते हैं।

■ **जीडीपी और आईआईपी के आधार वर्ष बदलने से आम आदमी को क्या लाभ?**
इससे यह साफ होगा कि किन सेक्टरों में उत्पादन और रोजगार बढ़ रहा है। सरकार बेहतर उद्योग और रोजगार नीतियां बना पाएगी, जिससे नौकरियों और आय के अवसर बढ़ सकते हैं।

■ **क्या सरकारी योजनाओं पर भी इसका असर पड़ेगा?**
हां। इन महत्वपूर्ण आंकड़ों से सब्सिडी, सामाजिक योजनाएं और राज्यों को मिलने वाला फंड वास्तविक जरूरतों के अनुसार तय किया जा सकेगा।

Hindustan Page No-13

किसान दिवस का मकसद अब तक अधूरा

23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। किसानों के मसीहा कहलाने वाले चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर हर साल यह दिवस मनाया जाता है, हालांकि अब उनकी तरह किसानों की समस्याओं की तरफ गंभीरता दिखाने वाले कम और इनके मुद्दों पर राजनीति करने वाले नेता अधिक हो गए हैं। अब तक शायद ही किसी सरकार ने किसानों की समस्याओं को हल करने और उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ने के ठोस प्रयास किए हैं, जबकि चौधरी साहब इसकी हिमायत लगातार करते रहे?

सरकारें किसानों की हमदर्द बनने के दावे तो करती हैं, पर जान-बूझकर राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए उनके मुद्दों को हवा देने का काम करती रहती हैं। अगर किसान अपने हक के लिए यूं ही सड़कों पर उतरते रहेंगे, तो खेती-बाड़ी में सुधार करने या पैदावार बढ़ाने पर कब ध्यान दे सकेंगे? अगर किसानों के हित वाली योजनाएं कारगर होतीं और उनका लाभ छोटे किसानों को मिलता होता, तो आज हमारे देश में सबका पेट भरने वाले अन्नदाता खुद भूखे न रहते, और न ही उनका जीवन विपन्न होता। वे आत्महत्या जैसे गलत कदमों के बारे में भी नहीं सोचते। जीडीपी में कृषि का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन किसानों को कभी प्राकृतिक प्रकोप का सामना करना पड़ता है, तो कभी सरकार की गलत नीतियों का। नतीजतन, लोगों का मन अब कृषि से ऊबने लगा है। जब किसानों को उनकी मेहनत का उचित फल नहीं मिलेगा, तो वे निराश ही होंगे न!

ऐसे में, सभी सत्ताधारियों और राजनेताओं को चाहिए कि वे किसानों की समस्याओं पर राजनीति करना बंद करें और किसानों की मुश्किलों को दूर करें। आज भी अपने देश में कमोबेश बारिश पर ही सिंचाई निर्भर है, जबकि प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण मौसम का चक्र बिगड़ गया है। लिहाजा, सरकार को कुछ बंदोबस्त करना चाहिए। इसी तरह, पानी के प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्जीवित करने के प्रयास भी होने चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों को चाहिए कि वे ऐसी तकनीक विकसित करें कि देश के हर राज्य में मौसम की बेरुखी से होने वाले फसलों के नुकसान से किसानों को बचाया जा सके, अर्थात जिस तरह मौसम का चक्र बदला है, उसी हिसाब से फसलों को चक्र भी बदला जाए। इसके साथ-साथ बाजार का लाभ भी किसानों को मिलना चाहिए कि औने-पौने दाम पर वे अपनी फसलें बेचने पर मजबूर न हो सकें। जाहिर है, किसानों की समस्याओं के समग्र समाधान की जरूरत है। तभी किसान दिवस का भी औचित्य है, अन्यथा ऐसे दिवसों का कोई महत्व नहीं।

राजेश कुमार चौहान, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
राष्ट्रीय किसान दिवस

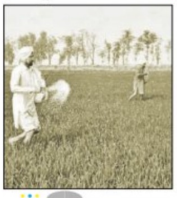

किसानों के हित में किए जा रहे कई काम

आधुनिक दुनिया जब चमकते महानगरों, डिजिटल तकनीक और तेज विकास की चकाचौंध में डूबी दिखाई देती है, तब किसान हमें हमारी जड़ों की ओर लौटने का संदेश देते हैं। वे ऐसे योद्धा हैं, जो सूरज की पहली किरण से पहले खेतों में उतर जाते हैं और देर शाम तक परिश्रम करते हैं। ऐसे में, राष्ट्रीय किसान दिवस केवल एक तिथि नहीं, बल्कि उस विचार का प्रतीक है, जो भारत को उसकी मिट्टी से जोड़ता है। किसानों का महत्व भारत की आत्मा में गहराई से रचा-बसा है। वे केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि देश की अर्थ व्यवस्था, सामाजिक संतुलन और खाद्य सुरक्षा का आधार स्तंभ हैं। भारत में करोड़ों किसान अपनी मेहनत से 146 करोड़ से अधिक लोगों का पेट भरते हैं, और राष्ट्रीय आय में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों की कृषि-उपज भारत को वैश्विक कृषि शक्ति के रूप में पहचान दिलाती है। किसान पर्यावरण के संरक्षक भी हैं, जो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखते हैं, जल संरक्षण करते हैं और जैव विविधता को जीवित रखते हैं।

निस्संदेह, जलवायु परिवर्तन आज कृषि की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है और किसान आर्थिक मोर्चे पर भी अनेक दबावों से घिरे हैं। मगर इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दी जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा देती है। कृषि अवसंरचना फंड से भंडारण, परिवहन और विपणन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। एटीएमए (एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी) जैसी योजनाएं किसानों को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देती हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म उन्हें बाजार की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। वर्ष 2025 में शुरू की गई प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और अन्य नई पहलों (जैसे-दलहन आत्मनिर्भरता मिशन) से आत्मनिर्भर कृषि को प्रोत्साहन मिला है।

बेशक, इन योजनाओं की सफलता तभी सुनिश्चित हो सकती है, जब इनका क्रियान्वयन बेहतर तरीके से हो। कई बार जानकारी के अभाव या जटिल प्रक्रियाओं के कारण किसान इनका पूरा लाभ नहीं उठा पाते। इतना ही नहीं, नाबार्ड और अन्य संस्थानों द्वारा दी जा रही ऋण व सब्सिडी सहायता किसानों के लिए संबल बन सकती हैं। किसान दिवस इस दिशा में संवाद, समीक्षा और सुधार का अवसर प्रदान करता है, ताकि नीतियां जमीन पर प्रभावी रूप से उतर सकें।

आरके जैन 'अरिजीत', शिक्षाविद

Hindustan Page No-10

रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेंगे डीआरडीओ : आरआरयू

नई दिल्ली में सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डीआरडीओ के चेयरमैन डा. समीर वी कामत की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन लिए राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. विमल एन पटेल (बाएं) और डीआरडीओ की महानिदेशक डा. चंद्रिका कौशिक। एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सोमवार को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा व आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अनुसंधान, शिक्षा व तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इस एमओयू पर 22 दिसंबर को साउथ ब्लाक, नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में हस्ताक्षर किए गए।

इसके तहत, दोनों संगठन संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, पीएचडी और फैलोशिप कार्यक्रमों और सुरक्षा बलों के लिए विशेष प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग करेंगे। यह पहल भारत की सुरक्षा तकनीकों में आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी। गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। डीआरडीओ सशस्त्र बलों और सुरक्षा एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का योगदान देता है। सेना ने साफ्टवेयर और एआइ आधारित समाधानों के विकास में सहयोग करने के लिए प्रमुख तकनीकी संस्थान नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एनएसयूटी) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

Dainik Jagaran Page No-3

भारत को कम व लंबी अवधि के युद्ध भी लड़ने को तैयार रहना चाहिए : सीडीएस

आतंकवाद रोकने को आपरेशन सिंदूर जैसे कम अवधि एवं उच्च तीव्रता वाले संघर्ष की तैयारी रहें

पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय विवादों के कारण संघर्ष के लिए भी तैयार रहना चाहिए

अनिल चौहान। फाइल

मुंबई, प्रेट्र : सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सोमवार को कहा कि आतंकवाद को रोकने के लिए भारत को आपरेशन सिंदूर जैसे कम अवधि एवं उच्च तीव्रता वाले संघर्ष, और अपने पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय विवादों के कारण लंबी अवधि के संघर्ष के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मल्टी-डोमेन आपरेशन अब एक विकल्प नहीं, बल्कि एक आवश्यकता होगी जहां एक डोमेन का प्रभाव तुरंत दूसरे डोमेन पर महसूस किया जाएगा।

आइआइटी बांबे में एक कार्यक्रम के दौरान जनरल चौहान ने पाकिस्तान या चीन का नाम लिए बिना कहा, "भारत को किस तरह के खतरों और चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए? यह दो तथ्यों पर आधारित होना चाहिए। हमारे दोनों विरोधी परमाणु हथियार संपन्न देश हैं। इसलिए हमें प्रतिरोध के उस स्तर का उल्लंघन नहीं होने देना चाहिए।" उन्होंने कहा कि भारत का दोनों पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय विवाद है। सीडीएस ने कहा, "आतंकवाद को रोकने के लिए हमें कम अवधि एवं उच्च तीव्रता वाले संघर्षों के लिए तैयार रहना चाहिए - आपरेशन सिंदूर जैसा ही कुछ। हमें भूमि केंद्रित लंबी अवधि के संघर्ष के लिए भी तैयार रहना चाहिए। फिर भी, हमें इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए।" सीडीएस ने कहा कि आतंकवाद और ग्रे जोन युद्ध एक खतरा बना रहेगा, जिसके लिए रक्षात्मक के साथ-साथ आक्रामक प्रतिक्रिया की भी आवश्यकता है। ग्रे जोन का तात्पर्य आम तौर पर एक ऐसे अस्पष्ट स्थान से है जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में प्रत्यक्ष संघर्ष व शांति के बीच मौजूद होता है। उन्होंने कहा कि कई प्रौद्योगिकियां एक साथ युद्ध की प्रकृति और चरित्र को प्रभावित कर रही हैं।

नौसेना की ताकत बढ़ी, मिला स्वदेशी युद्धपोत 'अंजदीप'

- पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज अंजदीप 88 प्रतिशत तक स्वदेशी
- जीआरएसई ने पेश की रक्षा क्षेत्र में आत्म निर्भरता की मिसाल

चेन्नई में सोमवार को भारतीय नौसेना को अंजदीप युद्धपोत सौंपने के अवसर पर जीआरएसई और नौसेना के अधिकारी। एएनआइ

राज्य ब्यूरो, जागरण कोलकाता

रक्षा क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को मजबूत करते हुए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) लिमिटेड ने सोमवार को नौसेना को अपना पांचवां युद्धपोत 'अंजदीप' सौंप दिया।

एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट श्रृंखला का यह तीसरा, जीआरएसई द्वारा निर्मित 115वां और नौसेना को दिया गया 77वां युद्धपोत है। कर्नाटक के कारवार के पास स्थित अंजदीप द्वीप पर इसका नाम रखा गया है। पूर्वी नौसेना कमान के रियर एडमिरल गौतम मारवाहा (बीएसएम) ने इस युद्धपोत को स्वीकार किया। जीआरएसई ने 2025 में रिकार्ड कायम करते हुए कुल पांच युद्धपोत नौसेना को समर्पित किए हैं। लगभग 77 मीटर लंबा यह जहाज वाटरजेट द्वारा संचालित सबसे बड़ा नौसैनिक युद्धपोत है। हल्के टारपीडो, स्वदेशी पनडुब्बी रोधी राकेट और उथले पानी के सोनार से लैस है।

Dainik Jagaran Page No-3

अहम कदम

सरला एविएशन ने बेंगलुरु में शुरू किया परीक्षण, घंटों का सफर मिनटों में होगा तय हेलीकाप्टर की तरह सीधे उड़ान भर सकेगी और उतर सकेगी एयर टैक्सी

ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत की उड़ान, एयर टैक्सी का परीक्षण शुरू

मुंबई, प्रेट्र: तेजी से बढ़ते शहरीकरण, सड़कों पर वाहनों के दबाव और रोजमर्रा के ट्रैफिक जाम से जूझ रहे भारतीय शहरों में आवागमन एक बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसे में एयर टैक्सी जैसी उभरती तकनीक को भविष्य के समाधान के तौर पर देखा जा रहा है, जो कम समय में लंबी दूरी तय कर सड़क यातायात पर निर्भरता घटा सकती है। इसी दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए एयरोस्पेस स्टार्टअप 'सरला एविएशन' ने बेंगलुरु स्थित अपनी निर्माण सुविधा में एयर टैक्सी कार्यक्रम की ग्राउंड टेस्टिंग शुरू कर दी है।

सरला एविएशन ने जनवरी 2025 में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में अपनी प्रोटोटाइप एयर टैक्सी 'शून्य' का अनावरण किया था। कंपनी की योजना 2028 तक बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक-आफ एंड लैंडिंग (ई-वीटीओएल) एयर टैक्सी सेवाएं शुरू करने की है। गौरतलब है कि 2024 में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सी शुरू करने के लिए सरला एविएशन के साथ साझेदारी की थी।

कंपनी के अनुसार, उसने अपने आधे आकार के (7.5 मीटर विंगस्पैन) ई-वीटीओएल डिमांस्ट्रेटर एसवाइएलएसए एसवाइएल-एक्स1 की ग्राउंड टेस्टिंग शुरू की है। यह भारत में निजी क्षेत्र द्वारा विकसित सबसे बड़ा और उन्नत ई-वीटीओएल डेमांस्ट्रेटर बताया जा रहा है। यह सब-स्केल विमान संरचनात्मक मजबूती, प्रोपल्शन इंटीग्रेशन और सिस्टम-स्तरीय सुरक्षा ढांचे के परीक्षण के लिए तैयार किया गया है। सरला एविएशन का दावा है कि यह उपलब्धि लगभग नौ महीनों में और वैश्विक मानकों की तुलना में कम पूंजी में हासिल की गई है। यह परियोजना पूर्ण-आकार के 15 मीटर विंगस्पैन वाले विमान की दिशा में एक अहम सेतु मानी जा रही है, जिसे शुरुआत से ही सर्टिफिकेशन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

एयर टैक्सी की खूबियां

2028 तक इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी उतारने की तैयारी

30 किलोमीटर तक सफर एक बार में किया जा सकेगा

680 किलोग्राम अधिकतम भार ले जा सकेगी एयर टैक्सी

250 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकेगी

6 लोग एक बार में यात्रा कर सकेंगे, हवाई एंबुलेंस सेवा में भी काम आ सकेगी एयर टैक्सी

बेंगलुरु में परीक्षण से पूर्व एयर टैक्सी की जांच करते कंपनी के इंजीनियर। सौ. सरला एविएशन

****

पहली महिला पायलट के नाम पर बनी कंपनी

पेज»5

Dainik Jagaran Page No-1

आईआईटी-एम्स की एआई तकनीक इलाज को बनाएगी असरदार

वेंटिलेटर पर मरीजों के लिए एआई करेगा भविष्यवाणी

शोध

■ रणविजय सिंह

नई दिल्ली। गंभीर बीमारियों के कारण आईसीयू में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जूझ रहे मरीजों को फायदा होगा या नहीं, यह पूर्वानुमान लगाना आसान नहीं होता।

अस्पतालों में मरीजों के दबाव में कई बार ऐसे मरीज को आईसीयू की सुविधा नहीं मिल पाती, जिनकी जिंदगी बचाई जा सकती है। ऐसे में कई मरीज आईसीयू की सुविधा न मिल पाने से भी दम तोड़ देते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित मशीन लर्निंग टूल यह काम आसान करेगा।

आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग व एम्स के विशेषज्ञों ने मिलकर यह तकनीक विकसित की है। यह टूल डॉक्टरों को आईसीयू में जीवन रक्षक उपकरण (वेंटिलेटर) के सपोर्ट पर भर्ती मरीजों की स्थिति और इलाज से फायदा होगा या नहीं यह पूर्वानुमान लगाने में मदद करेगा। इस आधार पर डॉक्टरों को आगे की रणनीति तय करने में मदद मिलेगी।

यह शोध हाल ही में मेडिकल जर्नल (जर्नल ऑफ क्लीनिकल मॉनिटरिंग एंड कंप्यूटिंग) में प्रकाशित हुआ है। इसके माध्यम से आईसीयू में भर्ती मरीज की सेहत में सुधार का पूर्वानुमान भी लगा सकेंगे। आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉ. अमित मैहंदीरत्ता के नेतृत्व में यह शोध किया गया। इस शोध में अहम भूमिका निभाने वाली शोधकर्ता डॉ. शिवी मेंदीरत्ता ने बताया कि मौजूदा समय में डॉक्टर मरीज की हालत और जांच रिपोर्ट के आधार पर सोफा स्कोर (सीक्वेंशियल ऑर्गेन फेल्योर स्कोर) तैयार करते हैं। इस आधार पर डॉक्टर आईसीयू में भर्ती मरीज की सेहत के बारे में पूर्वानुमान लगाते हैं। शोध में कहा गया है कि आईसीयू में भर्ती मरीजों की निगरानी जरूरी है।

इसके फायदे

- डॉक्टरों को इलाज की आगे की रणनीति तय करने में सहायता मिलेगी
- आईसीयू में भर्ती मरीजों की सेहत में सुधार की संभावना का अनुमान मिल सकेगा
- आईसीयू में भर्ती के लिए मरीजों की स्थिति के बारे में पता चल सकेगा
- मरीजों के दबाव के समय आईसीयू संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा

ऐसे काम करेगा एआई टूल

- आईसीयू में वेंटिलेटर पर भर्ती मरीजों के क्लीनिकल डाटा का विश्लेषण करेगा
- मरीज को भर्ती लेने से पहले की गई जांच और 98 पैरामीटर को आधार बनाएगा
- इसे एम्स के आईसीयू में भर्ती मरीजों के वास्तविक डाटा पर परखा गया
- मशीन लर्निंग आधारित मॉडल से मरीज की स्थिति और इलाज से फायदा होने का पूर्वानुमान लगाएगा

आठ मशीन लर्निंग टूल का परीक्षण किया गया : विशेषज्ञों ने आठ मशीन लर्निंग टूल का इस्तेमाल कर आईसीयू में भर्ती मरीजों के डाटा का परीक्षण किया। डॉक्टरों द्वारा तैयार मरीजों के सोफा स्कोर से भी तुलनात्मक अध्ययन किया। इस दौरान पाया गया कि शाप (शेप्ली-एडिटिव-एक्सप्लेनेशन) आधारित केएनएन (के-नियरेस्ट-नेबर) मशीन लर्निंग टूल आईसीयू के मरीजों की सेहत का पूर्वानुमान लगाने में ज्यादा मददगार है।

Useful For Mains

जानें-समझें

भारत, चीन व संयुक्त अरब अमीरात

त्रिपक्षीय साझेदारी को लेकर पहल की उम्मीद

जनसत्ता संवाद

भारत, चीन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच नई तरह की साझेदारी का विकास हो रहा है। चीन-भारत गतिरोध के बीच ही संयुक्त अरब अमीरात एक अद्वितीय भू-आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। रणनीतिक तटस्थता और व्यापार-प्रथम व्यवहारिकता पर आधारित अपनी विदेश नीति को सफलतापूर्वक विकसित करते हुए, संयुक्त अरब अमीरात ने दोनों एशियाई महाशक्तियों के साथ गहरे, भरोसेमंद और स्वतंत्र संबंध स्थापित किए हैं। वह एक राजनीतिक मध्यस्थ के रूप में नहीं, बल्कि एक भू-आर्थिक जमानती के रूप में उभरा है, और इसकी भूमिका पूंजी प्रदान करने से अधिक है।

भरोसे का निर्माण

भारत और चीन - दोनों के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक गठबंधनों के कारण, संयुक्त अरब अमीरात भरोसे के जमानती के रूप में कार्य करने की अनूठी स्थिति में है। भारत और चीन दोनों ही संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने मजबूत संबंधों को बनाए रखने में रुचि रखते हैं, इसलिए उनके पास इसके संरक्षण में समझौतों का प्रोत्साहन है। यह संरचना एक अप्रत्यक्ष भरोसे का निर्माण करती है, जहां संयुक्त अरब अमीरात की विश्वसनीयता वाणिज्यिक जुड़ाव की गारंटी देती है। दोनों दक्षिण एशियाई शक्तियां साझा हितों को साकार कर पाती हैं।

विरोधाभास में संतुलन

भारत और चीन के बीच संबंध एशिया के सबसे बड़े विरोधाभासों में से एक है। दोनों राष्ट्र महाद्वीपीय पड़ोसी और सभ्यतागत रूप से समतुल्य हैं, और वित्त वर्ष 2024-2025 में उनका द्विपक्षीय व्यापार लगभग 128 अरब डालर था, जो गहरी आर्थिक सहनिर्भरता को दर्शाता है। फिर भी, यह आर्थिक वास्तविकता रणनीतिक अविश्वास की बढ़ती मात्रा की नींव पर टिकी है, जो दशकों पुराने सीमा विवाद से और भी गहरा हो गया है, जो 2020 में हिमालय में फिर से सामने आया।

द्विपक्षीय सहयोग और शर्त

अक्सर चीन की रणनीतिक सोच में भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के बजाय दक्षिण एशियाई शक्ति के रूप में देखने के कारण उसे तनाव के एक स्रोत की तरह देखा जाता है, जिससे दोनों देशों के बीच लगातार दूरी बनी रहती है। विदेश नीति में मूलभूत मतभेदों से ये समस्याएं और भी जटिल हो जाती हैं; बेजिंग अक्सर राजनीतिक विवादों को आर्थिक संबंधों से अलग रखता है, जबकि नई दिल्ली द्विपक्षीय सहयोग को अधिक समग्र रूप से परिभाषित करती है, जहां एक सुरक्षित सीमा स्वस्थ आर्थिक संबंधों के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

चीन की रणनीति

चीन की रणनीतिक गणना में भारत को एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के बजाय दक्षिण एशियाई शक्ति के रूप में देखा जाता है। चीन का यह दृष्टिकोण अमेरिका-चीन संबंधों में भी स्पष्ट है, जहां रणनीतिक भरोसे के बिना भी व्यापक व्यापार होता है। हालांकि, भारत के साथ स्थिति अलग है, जैसा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि सीमा पर शांति और स्थिरता की स्थिति बिगड़ने पर संबंध सामान्य नहीं रह सकते। सीमा की प्रधानता का यह सिद्धांत, भारत-चीन संबंधों को सार्थक रूप से मजबूत करने के लिए रणनीतिक भरोसे को अनिवार्य तत्त्व बनाता है, न कि वैकल्पिक। इसके बिना, अपार आर्थिक क्षमता राजनीतिक और सुरक्षा जोखिमों से सीमित रह जाती है।

भारत को लाभ की उम्मीद

त्रिपक्षीय ढांचे के तहत, भारत को अपने विकास के लिए संयुक्त अरब अमीरात और चीन की पूंजी के साथ-साथ चीनी प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्राप्त होगी। चीन विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी, उन्नत लाजिस्टिक्स और विशाल पूंजी भंडार प्रदान करता है। संयुक्त अरब अमीरात आधारित ढांचा भारत को राजनीति से मुक्त और विश्वसनीय प्रवेश द्वार प्रदान करेगा। संयुक्त अरब अमीरात अपनी स्थापित तटस्थता, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे, परिष्कृत वित्तीय केंद्रों और सुदृढ़ कानूनी प्रणालियों की पेशकश भी करता है।

(फाइल फोटो)

अक्तूबर 2024 में रूस में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद भारत और चीन ने सतर्क तरीके से संबंध सामान्य करने की दिशा में कदम बढ़ाए। दोनों देशों को इसी दिशा में आगे बढ़ना होगा। साथ ही, सीमा विवाद को लेकर जारी बातचीत में दोनों देशों को किसी भी अनावश्यक उकसावे से बचने की कोशिश करनी होगी। - *जयदेव रानाडे, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड।*

शंघाई हवाई अड्डे की घटना के बाद पैदा हुआ तनाव ऐसे समय में सामने आया है, जब भारत विदेशी निवेश नियमों में दी गई ढील की समीक्षा पर विचार कर रहा है। इसे भारत से जमीनी सीमा साझा करने वाले देशों से निवेश को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। भारत की विभिन्न देशों के साथ चल रही एफटीए कवायद पर चीन को गौर करना होगा।
- *मनोज केवलरमानी, कूटनीतिक मामलों के जानकार।*

विवाद जारी है

हाल में अरुणाचल प्रदेश की एक भारतीय महिला को चीन से होकर यात्रा करते समय शंघाई हवाई अड्डे पर 18 घंटे तक रोके जाने की घटना से विवाद खड़ा हो गया। चीनी अधिकारियों ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है इसलिए उसका भारतीय पासपोर्ट मान्य नहीं है और उससे चीनी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने को कहा गया। महिला ने बताया कि अक्तूबर 2024 में उसकी चीन यात्रा बिना किसी समस्या के हुई थी। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया और साफ कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है तथा उसके नागरिक भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा कर सकते हैं। सरकार ने चीनी पक्ष से आश्वासन मांगा कि भारतीय नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाएगा और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी। चीन ने दोहराया कि वह अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता जिसे वह 'दक्षिण तिब्बत' कहता है।

Jansatta Page No-7

सुपरनोवा परियोजना पूरी करने के लिए समिति गठित

■ प्रभात कुमार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरनोवा परियोजना के काम को पूरा करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की है। समिति की अगुवाई जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और एनसीएलटी अध्यक्ष जस्टिस एमएम कुमार करेंगे।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा, समिति तुरंत प्रभाव से अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी), लेनदारों की समिति (सीओपी) और सुपरटेक की निलंबित निदेशक मंडल की जगह लेगी और परियोजना के बचे हुए काम को पूरा कराएगी। कोर्ट ने

■ सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग किया

अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह फैसला दिया। पीठ ने कहा, मामले की पृष्ठभूमि और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायमित्र की सिफारिशों, घर खरीदारों के अधिकारों की रक्षा करते हुए सभी के हितों में संतुलन की जरूरत है। समिति में सिविल इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विशेषज्ञ डॉ. अनूप कुमार मित्तल और वित्तीय प्रबंधन क्षेत्र में विशेषज्ञ राजीव मेहरोत्रा सदस्य होंगे।

➤ रजिस्ट्री की उम्मीद जगी P06

Hindustan Page No-1

पाकिस्तान की बदहाली से उपजे खतरे

महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से बुरी तरह जूझते पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि वहां कभी भी बड़े नेताओं, सेना के परिवारों और अफसरों के लिए कोई मंदी नहीं आती। इसका कारण नेताओं और सेना की अकूत संपत्ति है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए क्रिप्टोकरंसी को कवच बनाने की तैयारी हो गई है।

ब्रह्मदीप अलूने

आतंकवाद, हिंसा, अस्थिरता, संवैधानिक व्यवस्थाओं का अभाव, गरीबी और पिछड़ेपन से जूझते पाकिस्तान के कई इलाकों में आज भी बहुत सारी लड़कियों की स्कूल तक पहुंच नहीं है। अर्थव्यवस्था बेहाल है और गंभीर आर्थिक संकट है। मुद्रास्फीति बढ़ रही है। लोग स्वास्थ्य सेवा सहित बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था अंतरराष्ट्रीय एजंसियों और मित्र देशों से उधार लिए गए पैसे पर चल रही है। पाकिस्तान की तीस फीसद से अधिक आबादी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में गंभीर अभाव से ग्रस्त है, जबकि लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रही है। महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी से बुरी तरह जूझते इस देश के बारे में यह भी कहा जाता है कि कभी भी यहां बड़े नेताओं, सेना के परिवारों और अफसरों के लिए मंदी नहीं आती। इसका सबसे प्रमुख कारण नेताओं और सेना की अकूत संपत्ति है, जिसे सुरक्षित रखने के लिए क्रिप्टोकरंसी को कवच बनाने की तैयारी हो गई है।

पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता और नीतिगत अनिश्चितता ने पूंजी के लिए असुरक्षित वातावरण बनाया है। ऐसे में जिनके पास साधन और संपर्क हैं, वे अपनी संपत्ति को देश में रखने के बजाय विदेश में सुरक्षित करना अधिक अच्छा मानते हैं। दूसरी ओर, वहां कर चोरी व्यापक समस्या रही है। जब राज्य स्वयं कर संग्रह में असफल रहता है और कानून का समान रूप से पालन नहीं होता, तब संपन्न वर्ग के लिए अपनी आय छिपाना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। यह छिपी हुई आय धीरे-धीरे विदेश में निवेश के रूप में बदल जाती है। परिणामस्वरूप, देश के भीतर विकास के लिए आवश्यक पूंजी बाहर चली जाती है। दूसरी ओर सरकार कर्ज और अंतरराष्ट्रीय सहायता पर निर्भर होती जाती है।

पाकिस्तानी नागरिकों के पास दुबई में बड़ी संख्या में संपत्तियां हैं, जिनका कुल मूल्य साढ़े बारह अरब अमेरिकी डालर है। दुनियाभर के कारोबारियों और नेताओं की गुप्त सौदेबाजी का खुलासा 2016 में हुआ था और इसके केंद्र में पाकिस्तान के कई नेता, उद्योगपति और सेना के अधिकारी थे। बाद में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान की कुछ बड़ी हस्तियां गुपचुप तरीके से दौलत बाहर ले गई। इस मामले में इमरान खान के कुछ सहयोगियों के नाम भी शामिल थे। काले धन को वैध बनाने, प्रतिबंधों से बचने और कर चोरी में मदद की वैश्विक कड़ियां जुड़ीं, तो पाकिस्तान की राजनीति में हलचल मच गई और यह बड़ा मुद्दा भी बना।

नवाज शरीफ ने 2017 में पनामा पेपर्स में नाम आने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे भ्रष्ट देशों में से एक बताया है, जहां सभी क्षेत्रों में यह बुराई व्याप्त है। संयुक्त राष्ट्र की एक रपट में सेना से जुड़े व्यवसायों को पाकिस्तान का सबसे बड़ा समूह बताया गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जून 2023 में देश को दिवालिया होने से बचाने में मदद करने के लिए सेना प्रमुख मुनीर को सार्वजनिक रूप से धन्यवाद दिया था। पाकिस्तानी सेना में जमीन हड़पने की लालसा इतनी अधिक है कि उनके जनरल सामंती जमींदारों की तरह व्यवहार करते हैं और उन्हें जमीन माफिया कहा जाता है।

यह एक ऐसा देश है जो आर्थिक संकट, कर्ज निर्भरता और मुद्रा अवमूल्यन से जूझ रहा है। क्रिप्टोकरंसी इस अविश्वास के वातावरण में राज्य-निरपेक्ष संपत्ति के रूप में सामने आती है। यह न किसी बैंक में रखी जाती है और न ही किसी एक देश के कानून के अधीन होती है। इसका नियंत्रण व्यक्ति के पास उसकी निजी डिजिटल कुंजी के माध्यम से रहता है। यही कारण है कि लोग इसे पूंजी सुरक्षा के एक साधन के रूप में देखते हैं। जब मुद्रा का तीव्र अवमूल्यन होता है या महंगाई बचत को निगलने लगती है, तब सीमित आपूर्ति वाली क्रिप्टोकरंसी लोगों को अपनी पूंजी के मूल्य को बचाए रखने का एक विकल्प प्रतीत होती है। सीमा पार पूंजी ले जाने के संदर्भ में भी क्रिप्टोकरंसी की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। पारंपरिक तरीकों में विदेशी मुद्रा नियम, सरकारी अनुमति, बैंकिंग प्रक्रिया और समय की लंबी देरी शामिल होती है। इसके विपरीत क्रिप्टो नेटवर्क के माध्यम से व्यक्ति कुछ ही मिनटों में बिना किसी मध्यस्थ के दुनिया के किसी भी हिस्से में मूल्य का हस्तांतरण कर सकता है।

> पाकिस्तान में क्रिप्टोकरंसी का मूल उद्देश्य आम नागरिकों को आर्थिक सशक्तीकरण देना नहीं, बल्कि राजनीतिक अभिजात्य और सैन्य प्रतिष्ठान के धन को अंतरराष्ट्रीय निगरानी से सुरक्षित रखना प्रतीत होता है। पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली पर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और पश्चिमी वित्तीय एजंसियों की सख्त निगरानी है। ऐसे में क्रिप्टोकरंसी सत्ता वर्ग के लिए धन छिपाने, स्थानांतरित करने और प्रतिबंधों से बचने का एक वैकल्पिक माध्यम बन सकती है। आम लोगों के लिए यह व्यवस्था लाभकारी नहीं है। पाकिस्तान की बड़ी आबादी आर्थिक रूप से असुरक्षित है, वित्तीय साक्षरता कम है और डिजिटल ढांचे की पहुंच सीमित है।

पाकिस्तान की लगभग पैसठ फीसद आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका कृषि, पशुपालन, खेतों में मजदूरी और उससे जुड़े छोटे व्यवसायों पर निर्भर है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था नकद लेन-देन, परंपरागत साहूकारी, आढ़ती प्रणाली और सीमित बैंकिंग तक ही सिमटी हुई है। डिजिटल बैंकिंग, इंटरनेट और स्मार्टफोन की पहुंच अब भी असमान और सीमित है। ऐसे में क्रिप्टोकरंसी जैसी जटिल, तकनीकी और अस्थिर वित्तीय व्यवस्था ग्रामीण पाकिस्तान के लिए लगभग अप्रासंगिक है। ग्रामीण आबादी की प्राथमिक समस्याएं बिल्कुल अलग हैं। जैसे बीज, खाद और डीजल की महंगाई, सिंचाई की कमी, जलवायु संकट, फसल का उचित मूल्य न मिलना, कर्ज का जाल और सरकारी सहायता का अभाव। क्रिप्टो इन समस्याओं का समाधान नहीं करता।

जब किसी देश की अर्थव्यवस्था का आधार ग्रामीण जीवन, कृषि उत्पादन और स्थानीय बाजार हों, तब क्रिप्टोकरंसी विकास का इंजन नहीं बनतीं। पाकिस्तान के संदर्भ में यह स्पष्ट है कि क्रिप्टोकरंसी न तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी और न ही देश को आर्थिक स्थिरता देगी। यह अधिकतर एक शहरी-आभिजात्य और सत्ता-संरक्षण परियोजना बन कर ही रह जाएगी, जिसका बोझ आखिरकार ग्रामीण और गरीब जनता पर पड़ेगा। अनियंत्रित पूंजी, क्रिप्टो और सट्टा अर्थव्यवस्था में असली उत्पादन की जगह वित्तीय जुगाड़ को समाधान समझा जा रहा है। क्रिप्टो को विकास का विकल्प बताना दरअसल यह स्वीकार करना है कि राज्य के पास संरचनात्मक सुधार की क्षमता नहीं बची। जाहिर है, पाकिस्तान में क्रिप्टोकरंसी को बढ़ावा देना सुधार की नीति कम और सत्ता-संरक्षण की रणनीति अधिक दिखती है। इससे न तो आम जनता का जीवन सुधरेगा और न ही देश आर्थिक स्थिरता की ओर बढ़ेगा। वास्तविक लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिनके पास पहले से शक्ति, सूचना और संसाधन मौजूद हैं, जबकि जोखिम का बोझ एक बार फिर आम नागरिकों पर ही पड़ेगा।

Jansatta Page No-6

चिंताजनक

लंबा समय बीतने के बावजूद खाली करवा पाने में असमर्थ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

तुगलकाबाद ही नहीं, कई ऐतिहासिक स्मारक अतिक्रमण की जद में

अनामिका सिंह
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक तुगलकाबाद में अतिक्रमण की समस्या लंबे समय से बनी हुई है। कई बार इसे हटाने के प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। हाल ही में सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआइ) से यह खुलासा हुआ कि दिल्ली में सिर्फ तुगलकाबाद ही नहीं, बल्कि कई अन्य केंद्रीय संरक्षित स्मारक भी अतिक्रमण की जद में हैं।

यह आरटीआइ 'पब्लिक प्रोटेक्शन मूवमेंट आर्गेनाइजेशन' के निदेशक जीशान हैदर ने दायर की थी। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) से पूछा कि 2015 से 2025 तक दिल्ली में कितने स्मारकों पर अतिक्रमण है और उसे हटाने के लिए क्या कार्रवाई हुई। इसके जवाब में एएसआइ ने कहा कि तुगलकाबाद के अलावा कोटला फिरोजशाह, राजपुर सेमेट्री, डी ऐरेमाओ सेमेट्री और कश्मीरी गेट पर भी अतिक्रमण हुआ है। एएसआइ के अनुसार इन स्मारकों पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ 'प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958' के तहत कार्रवाई होती है। एएसआइ ने आरटीआइ में बताया कि तुगलकाबाद में 30 अप्रैल और 1 मई 2023 को चलाए गए अभियान में बंगाली कालोनी की लगभग सौ बीघा भूमि अतिक्रमण से मुक्त करवाई गई। लेकिन अन्य स्मारकों से अतिक्रमण हटाने के प्रयासों का कोई ब्योरा नहीं दिया गया।

इससे स्पष्ट है कि बीते दस वर्षों में अन्य स्मारकों पर अतिक्रमण लगातार जारी है और एएसआइ इसमें असमर्थ रही है। आरटीआइ के जवाब में यह भी खुलासा हुआ कि जनवरी 2015 से 17 अक्तूबर 2025 तक दिल्ली सर्किल के अधीन आने वाले कुछ स्मारक गायब हो गए हैं। इनमें निकोल्सन प्रतिमा, बाराखंभा सेमेट्री और इन्वावाली गुमटी शामिल हैं। ये स्मारक पांडवकाल से लेकर ब्रिटिशकालीन इतिहास को समेटे हुए थे। अगर अतिक्रमण जारी रहा और एएसआइ इसमें असमर्थ रही है। आरटीआइ के जवाब में यह भी खुलासा हुआ कि जनवरी 2015 से 17 अक्तूबर 2025 तक दिल्ली सर्किल के अधीन आने वाले कुछ स्मारक गायब हो गए हैं। इनमें हस्तसाल की मीनार व बारादरी, मोठ मस्जिद सहित महरौली के कई स्मारक शामिल हैं।

फाइल फोटो : तुगलकाबाद किला

आरटीआइ के जवाब में यह भी खुलासा हुआ कि जनवरी 2015 से 17 अक्तूबर 2025 तक दिल्ली सर्किल के अधीन आने वाले कुछ स्मारक गायब हो गए हैं। इनमें निकोल्सन प्रतिमा, बाराखंभा सेमेट्री और इन्वावाली गुमटी शामिल हैं। ये स्मारक पांडवकाल से लेकर ब्रिटिशकालीन इतिहास को समेटे हुए थे। अगर अतिक्रमण इसी तरह जारी रहा और एएसआइ ने कदम नहीं उठाए, तो भविष्य में कई अन्य स्मारक भी खतरे में आ सकते हैं। अन्य कई इमारतें भी हैं अतिक्रमण की चपेट में केंद्रीय संरक्षित स्मारकों के साथ ही दिल्ली के कई अन्य ऐतिहासिक स्मारक जैसे डीडीए, एमसीडी या अन्य नगर निकायों के अधीन आते हैं वह भी अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं।

Jansatta Page No-4

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा

अरावली के 277 वर्ग किमी में ही खनन की इजाजत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोमवार को नए नियमों का समर्थन किया और कहा कि केंद्र सरकार यह पक्का करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि अरावली पर्वत शृंखला हरी-भरी बनी रहे। उन्होंने कहा कि खनन गतिविधि अरावली के 1,43,577.03 लाख वर्ग किलोमीटर में से 277 वर्ग किलोमीटर में यानी '0.19 फीसद क्षेत्र' में ही करने की अनुमति है।

सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरावली क्षेत्र में सतत खनन के लिए केंद्र की सिफारिशों को मंजूरी देने के बाद इन पहाड़ियों की सुरक्षा की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच यादव ने यह बात कही।

पत्रकारों से बात करते हुए यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही देश की सबसे प्राचीन अरावली पहाड़ियों और अरावली को लेकर एक तकनीकी समिति का गठन किया। इसका मकसद खनन को सीमित करना है। पहले ऐसा होता था कि किसी भी जगह खनन होता था, ये तय नहीं था कि अरावली पहाड़ी या अरावली क्या है।

पर्यावरण मंत्री ने इस मुद्दे पर कुछ वरिष्ठ नेताओं पर भ्रामक पोस्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं, कुछ हमारे वरिष्ठ

यादव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर दिए गए निर्णय में केवल खनन को लेकर बात कही गई है।

नेता लोग भी भ्रामक पोस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में खनन की अनुमति ही नहीं है। एनसीआर का मतलब है दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूहं और अलवर का हिस्सा। जब एनसीआर क्षेत्र में खनन की अनुमति ही नहीं है, तो उनका तथ्य ही झूठा है।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस निर्णय में इस नई परिभाषा को दिया है, उसी में कहा गया है कि अभी कोई नई खनन लीज नहीं दी जाएगी। केवल क्रिटिकल, रणनीतिक रूप से अहम और परमाणु खनिजों को लेकर ही अपवाद होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्णय का संदर्भ केवल और केवल खनन को लेकर है। इसमें अन्य मामले जैसे रिहाइश आदि शामिल नहीं हैं। पर्यावरण मंत्रालय की ओर उपलब्ध कराए गए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक अरावली राजस्थान के 20 जिलों में फैली हुई है और इसका कुल क्षेत्रफल 1,06,008.95 वर्ग किलोमीटर है।

Jansatta Page No-2

आरएलडीए व्यावसायिक स्थल विकसित करने में विफल रहा

राकेश शर्मा
नई दिल्ली, 22 दिसंबर।

रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) अपने गठन से मार्च 2023 तक एक भी व्यावसायिक स्थल विकसित नहीं कर पाया। यह खुलासा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की अंकेक्षण (आडिट) रपट से हुई है। साथ ही रपट में प्राधिकरण के पंचवर्षीय योजना (2017-22) को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं।

रपट के मुताबिक, रेल भूमि विकास प्राधिकरण का गठन अक्तूबर 2006 में रेल मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में किया गया। इसके गठन का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा सौंपी गई रेलवे भूमि को गैर-टैरिफ (शुल्क) उपायों के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग के लिए बाकी पेज 8 पर

कैग की रपट में खुलासा

रपट के मुताबिक, रेल भूमि विकास प्राधिकरण का गठन अक्तूबर 2006 में रेल मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में किया गया। इसके गठन का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा सौंपी गई रेलवे भूमि को व्यावसायिक उपयोग के लिए विकसित कर राजस्व उत्पन्न करना था।

Jansatta Page No-1

मनरेगा की जगह जरूरी था जी राम जी

निरंजन कुमार

समय की मांग के अनुरूप पुराने दीर्घकालीन कार्यक्रमों को नए आधुनिक परिवेश में ढालना आवश्यक होता है

गुंजन अग्रवाल

भारतीय दर्शन के अनुसार परिवर्तन ही एकमात्र स्थिरता है। प्रसिद्ध अमेरिकी राष्ट्रपति जान एफ कैनेडी का भी कथन है- 'परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो केवल अतीत या वर्तमान की ओर देखते हैं, वे निश्चित रूप से भविष्य में चूक जाते हैं।' तेजी से बदलती 21वीं सदी में 'यंग इंडिया' की जरूरतों, आकांक्षाओं और विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने 'विकसित भारतः जी राम जी-2025' (विकसित भारत गारंटी फार रोजगार एवं आजीविका मिशन, ग्रामीण) कानून बनाया है। हर दीर्घकालीन नीति की 15-20 वर्षों में समीक्षा और मूल्यांकन की जरूरत होती है। इतने समय में परिवार, समाज और देश एक पूरी पीढ़ी का बदलाव देख लेता है। नई पीढ़ी कुछ नई जरूरतों एवं आकांक्षाओं के साथ आती है। वर्तमान भारतीय समाज 'मिलेनियल्स', 'जेन जी' और 'जेन अल्फा' सभी को साथ लेकर चल रहा है। हम गत 15 वर्षों में पेन-पेपर की दुनिया से निकल डिजिटल युग और एआइ में प्रवेश कर चुके हैं।

समय की जरूरत के अनुरूप पुरानी दीर्घकालीन योजनाओं को नए आधुनिक परिवेश में ढालना जरूरी होता है। इन्हीं कारणों से 2005 से प्रभावी 'नरेगा' (जिसे 2009 में 'मनरेगा' कहा गया) की जगह मोदी सरकार ने 'वीबीः जी राम जी' कानून का श्रीगणेश किया। स्वाधीनता के बाद से ही जरूरत के हिसाब से विभिन्न योजनाओं के स्वरूप में बदलाव किए जाते रहे हैं। 1960 के दशक में तत्कालीन सरकार ने ग्रामीण रोजगार योजनाओं की शुरुआत की और 'ग्रामीण श्रमशक्ति कार्यक्रम' लागू किए गए। समय की मांग के अनुरूप समय-समय पर विभिन्न सरकारें इनमें फेरबदल करती रहीं। परिणामस्वरूप देश में 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम', 'ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (जवाहर रोजगार योजना, 1993)', 'संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना' और 'रोजगार आश्वासन योजना' इत्यादि लागू की गईं। 2005 में 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (नरेगा) कार्यक्रम शुरू किया गया। 2009 में इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़कर 'नरेगा' से 'मनरेगा' कर दिया गया।

नए और तेजी से बदलते आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिदृश्य में मनरेगा एक प्रभावी योजना के तौर पर खरी साबित नहीं हो पा रही थी। साथ ही इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा था। इसके अतिरिक्त मनरेगा एक कल्याणकारी गरीबी उन्मूलन कानून के रूप में सीमित था, जबकि आज का ग्रामीण युवा 'विकसित भारत-2047' के

अवधेश राजपूत

सपनों को साकार करने के लिए संकल्पित है। इन्हीं सबको ध्यान में रखकर जी राम जी बिल लाया गया। जी राम जी कानून की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह कृषि चक्रों के साथ सही तालमेल और ज्यादा रोजगार की गारंटी देता है। मनरेगा में जहां केवल 100 दिन की मजदूरी की गारंटी थी, वहीं जी राम जी में ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी है। साथ ही श्रमिकों और किसानों के बीच समन्वय को ध्यान में रखते हुए फसल कटाई और बोआई के समय श्रमिकों को 60 दिनों की छुट्टी का प्रविधान है, ताकि उन्हें कृषि संबंधी रोजगार भी मिले। इससे कृषि में रोजगार को मिलाकर श्रमिक अब कुल 185 दिन रोजगार प्राप्त कर सकते हैं।

मनरेगा की आलोचना होती थी कि यह अल्पकालीन राहत या कम टिकाऊ संपत्ति बनाने तक सीमित है। बिना पूर्व तय मानकों के कार्यक्रमों से संसाधनों का दुरुपयोग बढ़ा। इससे अपेक्षित लाभ और ग्रामीण विकास नहीं हो पाया। मनरेगा में अब तक दस लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो चुके हैं, लेकिन बुनियादी ढांचा दिखाई नहीं देता। इस कमी को दुरुस्त करते हुए जी राम जी कानून में टिकाऊ संपत्ति निर्माण पर जोर दिया गया है, ताकि सतत विकास हो सके। अब चार श्रेणियों- जल संरक्षण, आधारभूत संरचना, आजीविका और प्राकृतिक आपदा से जुड़े कार्य तय किए गए हैं। नए कानून में 40 के बजाय 50 प्रतिशत खर्च निर्माण सामग्री पर होगा। इनका निर्णय दिल्ली में बैठे लोग नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर एक 'ग्राम समिति' कार्यक्रम तय करेगी।

मनरेगा में मजदूरी भुगतान में देरी की बड़ी समस्या थी। इससे श्रमिक वर्ग परेशान रहता था। जी राम जी में मजदूरी भुगतान साप्ताहिक या पाक्षिक रूप से अनिवार्य होगा। फिर डिजिटल माध्यम से मजदूरी भुगतान का प्रविधान भ्रष्टाचार की संभावना को खत्म करेगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि मनरेगा में कुछ राज्यों में ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया गया। जी राम जी बायोमीट्रिक अटेंडेंस, संपत्ति की जियो-टैगिंग और रियल-टाइम डैशबोर्ड के उपयोग का प्रविधान करता है। इससे भ्रष्टाचार और फर्जी लाभार्थियों में निश्चित रूप से कमी आएगी। इसके अलावा मनरेगा की तरह जी राम जी भी कानून श्रमिकों को समय पर काम नहीं मिलने पर उनके बेरोजगारी भत्ता प्रविधानों को जारी रखता है और अधिकार-आधारित हकदारी को प्रशासनिक दक्षता के साथ संतुलित करता है। मनरेगा की एक अन्य कमी थी, केंद्र और राज्यों का अपेक्षाकृत कम समन्वय और राज्यों में जवाबदेही का अभाव। नई योजना में पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्र सरकार 90 प्रतिशत योगदान करेगी, केवल 10 प्रतिशत राज्य देंगे। बाकी राज्यों को केंद्र 60 प्रतिशत देगा। राजनीतिक-मनोवैज्ञानिक आकलन के अनुसार जब अपना पैसा लगता है तो कार्य की गुणवत्ता निश्चित बेहतर होती है।

विपक्षी दलों के विरोध में कहीं न कहीं यह भाव भी है कि नए कानून का नाम 'राम' पर क्यों रखा गया है। देश में नई योजनाओं-कार्यक्रमों के लिए नए नाम रखने की परंपरा रही है। जी राम जी नाम से गांधीजी की कहीं अवमानना नहीं होती, क्योंकि नया नाम तो स्वयं गांधीजी के आराध्यदेव प्रभु राम पर आधारित है। जी राम जी कानून रोजगार गारंटी का विस्तार करके, वित्तीय अनुशासन को मजबूत करके, तेज भुगतान सुनिश्चित करके, काम को कृषि चक्रों के साथ जोड़कर और फोकस को अल्पकालिक राहत से टिकाऊ ग्रामीण विकास की ओर ले जाकर रोजगार और ग्रामीण विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प दिखाता है।

(प्रो. कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय में डीन प्लानिंग और डा. गुंजन लक्ष्मीबाई महाविद्यालय में अर्थशास्त्र की प्राध्यापिका हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8

शोधार्थी

भारत–अफ्रीका संबंधों में एक निर्णायक क्षण

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में जार्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा की है। विशेष रूप से पीएम की इथियोपिया यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी बहुत मजबूत हुई है और कई क्षेत्रों में नए अवसर खुले हैं। इस ऐतिहासिक यात्रा से एक बात स्पष्ट हुई है कि भारत और इथियोपिया केवल साझेदार नहीं, बल्कि एक–दूसरे की प्रगति में सहभागी भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया संपन्न यह यात्रा दोनों देशों के बीच एक नए अध्याय का आरंभ है। अब यह हम सभी नीति–निर्माताओं, व्यापार जगत, संस्थानों और नागरिकों की जिम्मेदारी है कि इस दृष्टि को वास्तविकता में बदलें

भारत के लिए इथियोपिया बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री की यात्रा के विशेष मायने हैं। बीते सप्ताह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इथियोपिया समेत कई अन्य देशों की यात्रा पर गए थे। इस दौरान पीएम मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान (द ग्रेट आनर निशान आफ इथियोपिया) प्रदान किया गया। फाइल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की हालिया संपन्न इथियोपिया यात्रा केवल एक कूटनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि यह भारत–अफ्रीका संबंधों को नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण क्षण है। ऐसे समय में जब वैश्विक सत्ता संतुलन बदल रहा है और नई साझेदारियां आकार ले रही हैं, यह यात्रा भारत की उस स्पष्ट सोच को दर्शाता है जिसमें अफ्रीका को उसकी विदेश नीति के केंद्र में रखा गया है। जनसंख्या, इतिहास और क्षेत्रीय प्रभाव के कारण इथियोपिया इस दृष्टि का स्वाभाविक साझेदार है।

भारत के लिए इथियोपिया केवल अफ्रीका का एक देश नहीं, बल्कि 'हार्न आफ अफ्रीका' का प्रवेश द्वार है। यह क्षेत्र समुद्री संपर्क, वैश्विक व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में इथियोपिया ने राजनीतिक, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई बदलाव देखे हैं। तमाम तरह की चुनौतियों के बावजूद यह देश अफ्रीका के सबसे संभावनाशील देशों में गिना जाता है। मोदी की यात्रा इस बात का संकेत है कि भारत इथियोपिया की दीर्घकालिक क्षमता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में उसकी भूमिका पर भरोसा करता है।

अदीस अबाबा में रणनीतिक संवाद : प्रधानमंत्री की इथियोपियाई नेतृत्व के साथ हुई बातचीत व्यापक और भविष्य पर केंद्रित रही। सुरक्षा सहयोग, समुद्री जागरूकता, आतंकवाद–रोधी प्रयास और शांति निर्माण जैसे विषयों पर विशेष चर्चा हुई। भारत अफ्रीकी संघ में इथियोपिया की भूमिका को महत्वपूर्ण मानता है और क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने में उसे एक प्रमुख साझेदार के रूप में देखता है। इस यात्रा के दौरान भारत ने इथियोपिया की शांति और सुलह की प्रक्रियाओं को समर्थन देने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। भारत हमेशा अफ्रीका–नेतृत्व और अफ्रीका–स्वामित्व वाले समाधानों का पक्षधर रहा है और बिना किसी शर्त के विकास सहयोग में विश्वास करता है।

विकास सहयोग : दोनों देशों के बीच विकास सहयोग के केंद्र में जनता को रखा गया है। भारत-इथियोपिया विकास सहयोग का माडल शोषण या कर्ज–आधारित नहीं है। इसका उद्देश्य स्थानीय क्षमताओं का निर्माण करना है– कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा, कृषि आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा को मजबूत करना जैसे मुद्दों को इसमें शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री ने भारत की ऋण सहायता और अनुदान परियोजनाओं का उल्लेख किया, जिनसे चीनी उद्योग, वस्त्र, ग्रामीण विद्युतीकरण और रेलवे जैसे क्षेत्रों में बदलाव आया है। भारत की डिजिटल सार्वजनिक संरचना इथियोपिया के डिजिटल भविष्य के लिए नई संभावनाएं खोलती है।

आर्थिक सहयोग को नई गति : इथियोपिया के औद्योगिक पार्क, लाजिस्टिक्स कारिडोर और उभरता उद्योग भारत की विनिर्माण और तकनीकी क्षमताओं के साथ स्वाभाविक रूप से मेल खाते हैं। इस यात्रा ने दवा उद्योग, आइटी सेवाएं, वस्त्र, कृषि–प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, खनन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भारतीय निवेश को प्रोत्साहित किया। व्यापार सुविधा, कारोबार की सहजता और निजी क्षेत्र की भागीदारी पर नए सिरे से संवाद शुरू हुआ है। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि निवेश टिकाऊ और पारस्परिक लाभ वाला हो, ताकि इसका सीधा लाभ वहां की जनता को मिले।

भारतीय प्रवासी समुदाय से विशेष जुड़ाव : इथियोपिया में भारतीय समुदाय अफ्रीका के सबसे पुराने प्रवासी समुदायों में से एक है। शिक्षकों, व्यापारियों और पेशेवरों ने दशकों से स्थानीय समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत के मूल्यों का सच्चा प्रतिनिधि बताया। प्रवासी भारतीयों से संवाद ने यह स्पष्ट किया कि भारत उनकी भूमिका को सम्मान और कृतज्ञता के साथ देखता है। उनकी सफलता इथियोपिया में भारत के प्रति विश्वास और स्नेह को दर्शाती है।

सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध : भारत और इथियोपिया के बीच प्राचीन सभ्यतागत संबंध रहे हैं– प्राचीन समुद्री व्यापार मार्गों से लेकर सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आदान–प्रदान तक। इस यात्रा ने शैक्षणिक सहयोग, विरासत संरक्षण और युवा–आधारित पहलों को नई ऊर्जा दी। योग, आयुर्वेद, सिनेमा और भारतीय संस्कृति को इथियोपिया में पहले से ही अपनाया जाता रहा है। प्रधानमंत्री की यात्रा ने इस सांस्कृतिक संबंध को और गहरा किया। इसे इस लिहाज से भी समझा जा सकता है कि इथियोपिया ने भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है।

इथियोपिया के प्रधानमंत्री डा. अबी अहमद अली ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को महान सम्मान निशान (द ग्रेट आनर निशान आफ इथियोपिया) से सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले प्रधानंमत्री मोदी विश्व के पहले वैश्विक राष्ट्राध्यक्ष हैं। संभवतः यही कारण है कि पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत और इथियोपिया के बीच हजारों वर्षों से संपर्क, संचार और आदान–प्रदान रहा है। भाषाओं और परंपराओं से समृद्ध हमारे दोनों देश विविधता में एकता के प्रतीक हैं। दोनों देश शांति और मानवता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। इथियोपिया की निर्यात सफलता और भारत की बाजार–तकनीक दक्षता दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक सहयोग सुनिश्चित करती है।

भविष्य की साझेदारी : यह यात्रा केवल प्रतीकात्मक नहीं है। यह एक साझा भविष्य का खाका है– जिसमें जलवायु अनुकूलन, फिनटेक, स्टार्ट–अप, कौशल विकास, स्वच्छ ऊर्जा और क्षेत्रीय शांति जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत और इथियोपिया ने विश्वास, समानता और समावेशी विकास पर आधारित साझेदारी का रास्ता चुना है।

मुस्लिम देशों से रिश्तों के बड़े मायने

कौसर जहां
अध्यक्ष, दिल्ली हज कमेटी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने वह कर दिखाया है, जो दशकों तक असंभव माना जाता रहा। पीएम मोदी के जार्डन, इथियोपिया और ओमान के हालिया दौरे से एक बार फिर साबित हो गया कि मुस्लिम देशों के साथ भारत के रिश्ते आज जिस भरोसे, सम्मान और आत्मीयता के स्तर पर पहुंचे हैं, वह केवल कूटनीतिक सफलता नहीं, बल्कि ऐतिहासिक परिवर्तन है। वस्तुतः नरेन्द्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने खाड़ी और इस्लामी देशों से रिश्तों को औपचारिकता से निकालकर रणनीतिक साझेदारी में बदला। उनकी संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की यात्रा में आतंकवाद पर साझा रुख देखने को मिला और ऐतिहासिक समझौते हुए। पीएम मोदी सऊदी अरब भी गए और सऊदी से भी सामरिक सहयोग, निवेश और सुरक्षा साझेदारी का नया अध्याय शुरू हुआ। उनकी कतर, ओमान, बहरीन की यात्राओं में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता मिली।

ये यात्राएं यह स्पष्ट करती हैं कि मुस्लिम देशों के साथ भारत का रिश्ता अब केवल ऊर्जा आयात तक सीमित नहीं, बल्कि भरोसे और साझेदारी पर आधारित है। यही वजह है कि आपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के लाख प्रयास के बावजूद उसे मुस्लिम देशों का साथ नहीं मिला। वहीं, पीएम मोदी की सूझ-बूझ ने भारत को संघर्ष की स्थिति में मीलों आगे रखा। यही नया भारत है और यही विकसित भारत का रोडमैप है, जहां मोदी के राष्ट्रप्रथम के विजन को व्यापक कूटनीतिक समर्थन भी मिला है। पीएम मोदी को मुस्लिम देशों में जिन सम्मानों से नवाजा गया, वे किसी व्यक्ति को नहीं, बल्कि भारत को दिए गए सम्मान हैं। पूर्व में पीएम मोदी को यूएई का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान, बहरीन, मिस्र और अन्य मुस्लिम देशों के राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है। यह वही इस्लामी दुनिया है, जिसे लेकर वर्षों तक यह भ्रम फैलाया गया कि भारत उनसे कट रहा है, जबकि पीएम मोदी की दूरदर्शिता ने दिखा दिया कि वास्तविकता इसके ठीक उलट है।

वस्तुतः पिछले 12 वर्षों में देखें तो भारत में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राजनीति विकास, रणनीति और कूटनीति के स्तर पर सबको साथ लेकर चलने की रही है। देश के भीतर भी सरकार की योजनाओं का लाभ मुस्लिम समाज को बड़े पैमाने पर मिला है। केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं में मुस्लिम बड़ा लाभार्थी वर्ग है। इन योजनाओं में धर्म नहीं, जरूरत आधार रहा। तमाम आंकड़े गवाह हैं कि आज मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभार्थी है। भाजपा सरकार में मुस्लिम समाज की अनदेखी की 'शिकायत' का नैरेटिव कमजोर पड़ गया है।

जब मुस्लिम देश भारत के नेतृत्व का सम्मान कर रहे हों, पैगंबर साहब के खानदान द्वारा पीएम मोदी का स्वागत-सम्मान हो, देश के भीतर मुस्लिम समाज योजनाओं का लाभ पा रहा हो, तो फिर यह कहना कि 'मुस्लिमों के साथ भेदभाव हो रहा है' केवल विपक्ष की आधारहीन तथ्यों से परे राजनीतिक शिकायत बनकर रह जाती है। वास्तविकता यह है कि मोदी सरकार ने मुस्लिम समाज को वोट बैंक नहीं, भागीदार नागरिक के रूप में देखा है।

पीएम मोदी की मुस्लिम देशों की यात्राएं, उन्हें मिले सर्वोच्च सम्मान, पैगंबर साहब के वंशज द्वारा दिया गया अभिनंदन और देश के भीतर मुस्लिम लाभार्थियों की सच्चाई– इन सबको जोड़कर देखें तो एक बात साफ है कि अब मुस्लिम समाज के नाम पर 'अलगाव और शिकायत' की राजनीति का नैतिक आधार कमजोर पड़ चुका है। नया भारत संवाद, सम्मान और विकास की राह पर चल रहा है और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है।

जागरण विशेष

ऊर्जा, रोजगार और स्वच्छता का मजबूत आधार बना गोबर–धन

उत्तराखंड ने गोबर व गीले कचरे के सही प्रयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दी नई दिशा

अश्वनी त्रिपाठी • जागरण

देहरादून: पहाड़ के गांवों में कभी भार समझा जाने वाला गोबर और गीला कचरा अब विकास की नई कहानी लिख रहा है। जो अपशिष्ट कल तक पर्यावरण के लिए चुनौती था, वह ग्रामीण अंचलों में ऊर्जा, रोजगार और स्वच्छता का मजबूत आधार बन गया है। बायोगैस प्लांट अब वैकल्पिक ऊर्जा का साधन ही नहीं, ग्रामीण आर्थिकी का प्रभावी विकास माडल भी बन चुके हैं। यहां के लोगों ने इसे खुशहाली का जरिया बना लिया है।

गोबर-धन को अपनाने में उत्तराखंड ने उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात समेत कई राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। गोबर गैस संयंत्रों की संख्या जहां अन्य राज्यों में कम होती जा रही है, वहीं उत्तराखंड में साल दर साल संयंत्र बढ़ रहे हैं। वर्तमान में राज्य में 8,362 बायोगैस प्लांट स्थापित हैं। प्रतिदिन करीब 880 टन ठोस कचरा निकलता है, जिसमें लगभग 63 प्रतिशत जैविक कचरा होता है। पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों और पशुपालकों की भागीदारी के कारण कचरे का स्रोत-स्तर पर संग्रह संभव हुआ। गंदगी, दुर्गंध और बीमारियों की वजह बनने वाले कचरे को बायोगैस प्लांट ने ऊर्जा और खाद में बदलने का रास्ता दिखाया है। स्रोत पर ही निस्तारित होने से कचरा ढोने और डंपिंग का बोझ कम हुआ है। स्थानीय रोजगार का सृजन करने में उल्लेखनीय सफलता मिली है। इनसे मिलने वाली रसोई गैस ने ग्रामीण परिवारों के ईंधन खर्च को काफी कम किया है। एलपीजी सिलिंडर, लकड़ी और कोयले पर निर्भरता घटने से परिवारों की बचत बढ़ी है। बायोगैस से बिजली उत्पादन होने से ऊर्जा पर होने वाला खर्च घटकर सीधे गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। इससे उच्च गुणवत्ता की जैविक खाद बनती है, जो किसानों की आय और मिट्टी दोनों को समृद्ध बना रही है। खेती की लागत घट रही है और उत्पादन में सुधार हो रहा है। पशुपालकों के लिए गोबर अब अपशिष्ट नहीं, बल्कि कमाई का साधन बन चुका है।

15 साल में एक पाई खर्च नहीं

देहरादून के कालूवाला गांव के अरविंद चौहान बताते हैं कि उनके घर में 15 साल पहले बायोगैस कनेक्शन लगा था। तब से घरेलू गैस पर कोई भी खर्च नहीं किया गया। उन्होंने दो गायें पाल रखी हैं। उनसे दिनभर में करीब 45 किलो गोबर मिलता है, जिससे तीन घन मीटर का ड्रम आसानी से भर जाता है। ईंधन खर्च करने के बाद उन्हें भरपूर स्लरी भी मिल जाती है, जो फसलों के लिए सोना है। उन्होंने बताया, पिछले 15 सालों में इस प्लांट ने उन्हें आर्थिक रूप से बड़ी राहत पहुंचाई।

देहरादून के संगतियावाला में बायोगैस प्लांट • अरविंद चौहान

राज्य और बायोगैस प्लांट

उत्तराखंड	8,362
ओडिशा	5,966
गुजरात	5,427
उत्तर प्रदेश	3,594
हरियाणा	3,487
राजस्थान	2,404

(आंकड़े नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं)

बायोगैस परियोजनाओं ने ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। ईंधन पर निर्भरता घटी है, तो किसानों और स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ी है। बायोगैस से बिजली, खाना पकाने की गैस और जैविक खाद उपलब्ध होने से आर्थिकी को बढ़ावा मिला है और कचरा प्रबंधन सुधरने से पर्यावरण संरक्षण को बल मिला है। बायोगैस उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और हरित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभा रही है।

आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव, ऊर्जा

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

विद्रूपताओं को अपनाने वाला समाज

डा. विभा त्रिपाठी

कुछ महिलाओं द्वारा दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग के बीच आज भी नवविवाहिताओं को दहेज की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है

सामाजिक समस्या पर चिंतित सुप्रीम कोर्ट। फाइल

कहते हैं, सामाजिक कुप्रथाओं का कोई मजहब नहीं होता। हिंसा की कोई जाति नहीं होती। ये बातें तब फिर सही साबित होती दिखीं, जब हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने संवेदनशीलता दिखाते हुए संवैधानिक समानता और सामाजिक असमानता के बीच की गहरी खाई पाटने का प्रयास किया। हाल में अजमल बेग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि सामाजिक समस्याएं कभी खत्म नहीं होतीं, बल्कि उन पर समय की गर्द पड़ जाती है और हम कुछ अन्य समस्याओं को समसामयिक और ज्वलंत मानते हुए उनकी चर्चा में उलझ जाते हैं। 1961 में लंबी जद्दोजहद के बाद दहेज प्रतिषेध कानून अस्तित्व में आया और भारतीय दंड संहिता में उसके 25 वर्ष बाद (1986) दहेज हत्या के अपराध को जगह मिली।

हाल के दिनों में कुछ महिलाओं द्वारा दहेज प्रतिषेध कानून के दुरुपयोग के मामलों पर चर्चाओं ने इतना जोर पकड़ा कि हम भूल गए कि आज भी नवविवाहिताओं को दहेज की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। इस मामले में न्यायालय ने एक तरफ अपने से ऊंचे ओहदे वाले परिवारों में शादी की परंपरा का उल्लेख किया और यह बताना चाहा कि कई बार उसकी कीमत युवा महिलाओं को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। न्यायालय ने यह भी कहा कि जिस मुस्लिम समुदाय में दहेज का कोई प्रविधान ही नहीं है, उलटे जहां 'मेहर' की बात की गई है, उसी समुदाय में किसी महिला को जलाकर मार दिया जाना यह प्रमाणित करता है कि हमारा समाज विद्रूपताओं को अपनाने वाला समाज है। इसमें हम आदर्श से हर वक्त किनारा करते दिखाई देते हैं। कानूनी प्रविधानों तथा सामाजिक सोच में समानता न होने का प्रमाण हर बार दिखाई देता है। जब देश के विधि निर्माताओं को लगा कि यदि हम महिलाओं को जन्म से ही बराबर मानते हुए उन्हें पैतृक संपत्ति में बराबर का भागीदार बना देंगे तो दहेज की समस्या स्वतः ही खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। या तो पारिवारिक संबंध बचाए रखने के लिए महिलाओं को हलफनामा देना पड़ता है कि वे पैतृक संपत्ति में अपने हक की मांग ही नहीं करेंगी अथवा यदि मांग करेंगी भी तो परिवार स्वेच्छा से उन्हें यह अधिकार नहीं देगा और सर्वोच्च न्यायालय तक अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी।

समाज अभी भी आधी आबादी को बराबरी का पूरा दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आज भी दहेज की मांग जारी है और नवविवाहिताओं की हत्या के मामले भी सामने आते हैं। समाज यहीं नहीं रुकता, बल्कि जब एक महिला गर्भधारण करती है तो अनेक घरों में उसके संबंधी यही आस लगाए रहते हैं कि होने वाली संतान बेटा ही हो। पहली संतान के रूप में बेटी फिर भी स्वीकार हो जाती है, लेकिन दूसरी बार विधियों के दुरुपयोग की तलाश प्रारंभ हो जाती है, जो कई बार कन्या भ्रूण हत्या का कारण बनती है। शायद इसी कारण विश्व आर्थिक संगठन ने यह अनुमान लगाया है कि वैश्विक स्तर पर पूर्ण लैंगिक समानता 2150 तक ही आ पाएगी। यानी अभी 125 वर्ष और लगेंगे। क्या तब तक ऐसे ही नवविवाहित महिलाएं प्रताड़ित होंगी और बेटियां गर्भ में मारी जाती रहेंगी? यदि माता-पिता ने समाज से संघर्ष करते हुए उन्हें जन्म दे भी दिया तो क्या वे फिर दहेज की बिभीषिका का शिकार होंगी?

दहेज प्रतिषेध कानून एक पंथनिरपेक्ष अधिनियम है और हर पंथ के लोगों पर लागू होता है। यही वजह है कि अजमल बेग के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने एक साथ अनेक दिशानिर्देश जारी किए हैं। मसलन, स्कूली पाठ्यक्रम में ऐसे बदलाव किए जाएं, जिनसे लैंगिक रूढ़िवादिता समाप्त हो। आरंभ से संदेश जाए कि विवाह में दोनों पक्ष समान हैं और कोई भी दूसरे के अधीन नहीं है। यह संवैधानिक समानता की भावना जब तक सामाजिक समानता के धरातल पर चरितार्थ नहीं होगी, तब तक हम पूर्ण न्याय पाने की स्थिति में नहीं होंगे। सभी राज्यों में न केवल दहेज निषेध अधिकारियों की प्रभावी नियुक्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए, बल्कि उनके नाम, फोन नंबर और ई-मेल जैसी जानकारी स्थानीय स्तर पर व्यापक रूप से प्रसारित करने के साथ उन्हें संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। महिला एवं बाल कल्याण अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया जाए, ताकि दहेज मृत्यु और क्रूरता के मामलों के सामाजिक-मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझा जा सके और वास्तविक मामलों तथा झूठे अथवा दुरुपयोग वाले मामलों में अंतर किया जा सके। उच्च न्यायालयों को भी निर्देश दिया गया है कि वे दहेज मृत्यु और दहेज प्रताड़ना से जुड़े लंबित मामलों की समीक्षा कर उनके शीघ्र निपटारे के लिए कदम उठाएं। इसका तात्पर्य यह है कि समाज का हर परिवार अपने बच्चों को शिक्षा दे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करे और समानता के मजबूत ताने-बाने के साथ विवाह जैसे रिश्ते की बुनियाद डाले, ताकि पूरे समाज को यह संदेश मिले कि विवाह एक सामाजिक संस्था है और मातृत्व एक सामाजिक जिम्मेदारी। गृहस्थी की गाड़ी एक पहिये पर नहीं चल सकती, बल्कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। एक सुलझे हुए परिवार में ही एक सुलझा हुआ समाज बसता है।

(लेखिका काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि संकाय में प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

Dainik Jagaran Page No-8

प्रश्न (BPSC Mains)

भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता (FTA) के आर्थिक, रणनीतिक एवं सामाजिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। साथ ही इससे जुड़ी संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा करते हुए आगे की राह सुझाइए।
(शब्द सीमा: 400 शब्द)

उत्तर लिखने का आदर्श ढांचा

भूमिका (40–50 शब्द)
- FTA की संकल्पना: शुल्क कटौती/उन्मूलन, बाजार पहुंच, निवेश प्रवाह
- भारत–न्यूज़ीलैंड संबंधों में नया आयाम
- Indo-Pacific व आपूर्ति-श्रृंखला विविधीकरण का संदर्भ

I. FTA की प्रमुख विशेषताएँ (80–90 शब्द)
- **शुल्क उन्मूलन**: अधिकांश वस्तुओं पर आयात शुल्क में कटौती
- **सेवाएँ व निवेश**: आईटी, शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य
- **श्रम गतिशीलता**: कुशल श्रमिकों/छात्रों को अवसर
- **मानक व नियम**: SPS/TBT, बौद्धिक संपदा, डिजिटल व्यापार

II. भारत के लिए अवसर/लाभ (100–110 शब्द)

(क) आर्थिक
- कृषि-निर्यात (फल-सब्ज़ी, मसाले), फार्मा, टेक्सटाइल
- MSMEs को नए बाज़ार, निर्यात प्रतिस्पर्धा
- निवेश व तकनीक हस्तांतरण

(ख) रणनीतिक
- Indo-Pacific में भरोसेमंद साझेदारी
- चीन-निर्भरता घटाने में सहायक

(ग) सामाजिक/मानव संसाधन
- छात्रों/कुशल पेशेवरों के अवसर
- स्टार्ट-अप/इनnovation सहयोग

III. चुनौतियाँ/आशंकाएँ (80–90 शब्द)
- **कृषि संवेदनशीलता**: डेयरी पर प्रतिस्पर्धा का दबाव
- **घरेलू उद्योग**: सस्ते आयात से MSMEs पर असर
- **मानक अनुपालन**: SPS/TBT लागत
- **व्यापार असंतुलन**: आयात बढ़ने का जोखिम

IV. आगे की राह / सुझाव (70–80 शब्द)
- **फेज़्ड लिबरलाइज़ेशन** व संवेदनशील सूची
- **सेफगार्ड क्लॉज** व एंटी-डंपिंग उपाय
- **क्षमता निर्माण**: MSMEs, मानक अनुपालन सहायता
- **राज्य-स्तरीय निर्यात रणनीति** व लॉजिस्टिक्स सुधार
- **सेवा-निर्यात पर फोकस** (आईटी, शिक्षा)

निष्कर्ष (30–40 शब्द)
- संतुलित FTA विकास-समर्थक हो सकता है
- हित-संरक्षण + अवसर-सृजन का समन्वय आवश्यक
- रणनीतिक विश्वास के साथ आर्थिक लाभ संभव